घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर, वर्ष 23, अंक - 03- मंगलवार 03- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 , मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

राजस्थान में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत

झुंझुनूं में सड़क बनाते समय मशीन हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई

झुंझुनूं,02 नवम्बर 2026। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सोमवार सुबह सड़क बना रहे 8 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। 5 अन्य मजदूर झुलस गए। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। उदयपुरवाटी के एसएचओ रामपाल ने बताया-सड़क पर काम कर रही रोड़ी-बजरी मिक्सर मशीन का हाइड्रोलिक जैक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार से छू गया। इससे मशीन में करंट फैल गया और वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे में श्रमिकों की असामयिक मृत्यु पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स'पर कहा कि संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार,प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने और घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति,घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और शोकाकुल परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की।

15-15 लाख मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने पर सहमति

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा...मृतकों के आश्रितों को अलग-अलग योजनाओं में 15 लाख मुआवजा और एक-एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी है। विकास अधिकारी और तहसीलदार को राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाओं में लाभ देने के लिए कहा है। वन विभाग की जमीन पर बन रहे इस रास्ते को लेकर झुंझुनूं के डीएफओ को निर्देश दिए है कि संबंधित जनप्रतिनिधि से संपर्क कर रास्ते के डायवर्जन के प्रस्ताव को पोर्टल पर अपलोड करें। बातचीत के बाद परिजन शव लेने को तैयार हो गए और धरना खत्म कर दिया।

पहले रास्ते से दूर थी 11केवी लाइन,कुछ दिन पहले ही बदली : हादसे के बाद ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण रोहिताश्व ने बताया...11केवी की लाइन पहले रास्ते से दूर थी, लेकिन कुछ दिन पहले इस लाइन को बदलकर रास्ते के ऊपर से लिया गया था। तार नीचे होने के कारण ये बड़ा हादसा हो गया।

गहलोत ने हादसे पर जताया दुःख

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि उदयपुरवाटी के छापोली गांव में मजदूरों की करंट लगने से हुई मौत बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच आवश्यक है, ताकि यह पता चल सके कि सड़क निर्माण के दौरान हादसा कैसे हुआ और इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। गहलोत ने राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।



प्रधानमंत्री ने झुंझुनूं हादसे पर जताया शोक,मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख की सहायता



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सड़क निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से आठ श्रमिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि झुंझुनूं में हुए हादसे में लोगों की मौत से वह बेहद दुःखी हैं। उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान बजरी मिलाने वाली मशीन के 11 हजार वोल्ट की उच्च क्षमता वाली बिजली लाइन के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। इसमें आठ श्रमिकों की मौत हो गई,जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसा छापोली और कदमकुंड को जोड़ने वाली सामुदायिक सहभागिता से बनाई जा रही सड़क के निर्माण के दौरान हुआ।

चुनौतियों के बावजूद भारत की ग्रोथ मजबूत : प्रधानमंत्री मोदी

कोविड हो या पश्चिम एशिया संकट,140 भारतीयों ने देश को संकट से निकाला



नई दिल्ली,02 नवम्बर 2026। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का इनॉगरेशन किया। उन्होंने कहा कि इस साल दुनिया में एनर्जी शॉक की ही चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल इकोनॉमी ने ऐसे संकटों का सामना किया है, जो पहले कभी नहीं हुए। कोविड-19 से लेकर पश्चिम एशिया के संकट तक दुनिया को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे गर्व है कि 140 करोड़ भारतीयों ने देश को इन मुश्किल समय से निकलने में मदद की है। कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने एक मजबूत ग्रोथ ट्रैक बनाए रखा। अगर हमने पिछले दशक में क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं किया होता और नए सिस्टम नहीं बनाए होते तो हमारी इकोनॉमी पर इन संकटों का असर कहीं ज्यादा गंभीर होता।

पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें...

- 2021 के समिट में, भारत ने 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का संकल्प लिया था।
- पेरिस एग्रीमेंट के तहत, भारत ने अपनी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% नॉन-फॉसिल फ्यूल सोर्स से पूरा करने का भी वादा किया था। हमने यह टारगेट 2025 में, तय समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया।
- मैं चाहता हूं कि भारत के अनुभव इसका लाभ पूरी मानवता को मिले। इस क्षेत्र में भारत की जो सफलताएं हैं, वो दुनिया के अनेक देशों को काम आएगी।
- हमने फरवरी 2024 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की, इसके तहत एक करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। पिछले 24-25 महीनों में ही 65 लाख से ज्यादा घर अभियान से जुड़ चुके हैं।
- हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में खाली जमीन पर किसान सोलर पैनल लगाए। सौर क्रांति का ये नया दौर सिर्फ अपनाने का नहीं है। ये इनोवेशन पर भी निर्भर है।

दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे

अस्पताल-वृद्धाश्रम जैसे साइलेंस जोन में रोक,सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे साल परमिशन दी

नई दिल्ली,02 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों,नर्सिंग होम,प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों,वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी 'नो-क्रैकर जोन'घोषित किया जाए। इनकी उचित मार्किंग की जाए और लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 15 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे चलाने को लेकर आदेश दिया था। इसमें दो दिन 19 और 20 अक्टूबर को ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी।



ग्रीन पटाखे जलने से कम धुआं निकलता है : ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं,जिन्हें सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाने के लिए बनाया जाता है। इनमें हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कम किया जाता है, जिससे इनके जलने पर कम धुआं और कम हानिकारक गैसें निकलती हैं।

नौसेना को मिलेंगे 8 नए युद्धपोत...मिसाइल और सेंसर सिस्टम से लैस होंगे

दो भारतीय कंपनियां बनाएंगी,रक्षा मंत्रालय से 53,866 करोड़ का करार

नई दिल्ली,02 नवम्बर 2026। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 नए युद्धपोत बनाने के लिए 53,866.50 करोड़ के समझौते पर साइन किए हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट यानी नई पीढ़ी के युद्धपोत होंगे। इनमें आधुनिक मिसाइल,हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए जाएंगे। इन युद्धपोतों को बनाने की जिम्मेदारी दो भारतीय कंपनियों को दी गई है। इनमें कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पांच और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तीन युद्धपोत बनाएगी। सोमवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस समझौते पर साइन किए गए।

दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रखेंगे...

नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट में आधुनिक मिसाइल,हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए जाएंगे। इनकी मदद से नौसेना हवा, समुद्र की सतह और पानी के नीचे से आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकेगी। इन जहाजों का इस्तेमाल समुद्री व्यापार के रास्तों की सुरक्षा, दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ कार्रवाई और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ये समुद्र के किनारे सैन्य अभियान चलाने और निगरानी रखने में भी मदद करेंगे।



भारत में बने सामान और तकनीक का इस्तेमाल होगा

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक,इन युद्धपोतों में 70% से ज्यादा सामान भारत में बनाया जाएगा। इनका डिजाइन भी भारतीय नौसेना तैयार करेगी। युद्धपोतों को 2030 तक नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रोजेक्ट सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है। इससे देश में युद्धपोत बनाने के काम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही,रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने और भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

10 साल में 532 लाख काम के दिनों के बराबर रोजगार मिलने का अनुमान

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन युद्धपोतों के निर्माण से अगले 10 साल में शिपयार्ड में 72 लाख और उनसे जुड़े उद्योगों में 460 लाख काम के दिनों के बराबर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अलग-अलग लोगों को मिलाकर कुल 532 लाख दिनों तक काम मिलेगा। इस परियोजना में सरकारी रक्षा कंपनियों के साथ निजी शिपयार्ड और भारतीय उद्योग भी शामिल होंगे। इससे छोटे और मध्यम कारोबारों को भी काम के अवसर मिलेंगे।

फ्लाइट टिकट 700 प्रतिशत बढ़ाने के दावे वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा... फ्लाइट से यात्रा मत करिए,आगे बढ़िए...

नई दिल्ली,02 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बढ़ते हवाई किराए को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के 700% तक किराया बढ़ने के दावे पर कोर्ट ने कहा,'आप हवाई यात्रा मत करिए। आगे बढ़िए।' जस्टिस जे.विक्रम नाथ की बेंच के सामने वकील ने दलील दी कि विमान का किराया 700% तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा जरूरी सेवा है और किराए में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों पर सुनवाई नहीं की और याचिका खारिज कर दी। भारत में हर साल करीब 24 करोड़ हवाई यात्राएं होती हैं। नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए के 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें 16.55 करोड़ घरेलू और 7.39 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्री यात्राएं शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को भारतीय वायुयान नियम, 2026 का गजट जारी किया है। नए नियमों के तहत विमानन कंपनियों को हवाई टिकटों का किराया तय करने की छूट दी गई है। एयरलाइंस को किराया बढ़ाने या घटाने के लिए सरकार से पहले अनुमति नहीं लेनी होगी। हालांकि,किसी अपरिहार्य स्थिति में सरकार विमानन कंपनियों को किराए को लेकर निर्देश दे सकती है। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।



मप्र से राज्यसभा के लिए निर्दलीय राजकुमार लोहानी ने ठोकी ताल,कांग्रेस का समर्थन

भोपाल,02 नवम्बर 2026। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए होने वाला उपचुनाव अब दिलचस्प हो गया है। भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी ने सोमवार को विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने राजकुमार लोहानी को समर्थन देने का फैसला किया है। उनके नामांकन में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे प्रस्तावक बने। इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ अकील,अभिजीत शाह,सुरेंद्र सिंह हनी बघेल सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकुमार लोहानी के मैदान में उतरने से राज्यसभा उपचुनाव में मुकाबले की स्थिति बन गई है। हालांकि,विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। इसके बावजूद कांग्रेस ने लोहानी को समर्थन देकर भाजपा उम्मीदवार के सामने चुनौती पेश करने का राजनीतिक फैसला लिया है। उपनेता प्रतिपक्ष कटारे ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की सोमवार को अंतिम तारीख थी। राजकुमार लोहानी ने चुनाव में कांग्रेस विधायकों से सहयोग मांगा है।

राहुल ने नकली संसद लगाई...उसके पीएम बन जाते,सोनिया जी के दिल को शांति मिल जाती,असली संसद में कभी नहीं बनेंगे : शाह

नई दिल्ली,02 नवम्बर 2026। अमित शाह सोमवार को हैदराबाद में'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'मार्च में शामिल हुए। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में नकली संसद लगाई। वे उसके ही पीएम बन जाते तो सोनिया जी के दिल को शांति मिल जाती। असली संसद में वे कभी पीएम नहीं बनेंगे। विपक्ष के एसआईआर विरोध के जवाब में भाजपा देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान चला रही है। इसका पहला चरण 22 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक चलेगा।

घुसपैठिए कांग्रेस के वोट बैंक,इन्हें निकालकर ही दम लेंगे : शाह

कांग्रेस पार्टी एसआईआर को रोककर देश की मतदाता सूची से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। ये घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं। राहुल जी जितना जोर लगाना है लगा लो,



भाजपा एक-एक घुसपैठिए को देश और वोटर्स लिस्ट से बाहर निकालकर दम लेगी। 3 करोड़ वोट बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं।

भाजपा 2014 में जीती, 2019 में जीती, तब क्या एसआईआर हुआ था : शाह ने कहा- राहुल जी कहते हैं कि हम (भाजपा) एसआईआर से जीते। जरा बताओ क्या 2014 में एसआईआर हुआ था। 2019 में जीते, तब भी एसआईआर नहीं हुआ था। 2024 में भी जीते, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, बंगाल,असम जीते। अब तेलंगाना भी जीतने वाले हैं।

नकली संसद में ही पीएम बन जाइए : शाह ने कहा...राहुल जी,दो दिन पहले आपने मॉक पार्लियामेंट की थी,अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि ये नकली संसद में आप एक बार पीएम बन जाओ,क्योंकि असली संसद में वे कभी बन नहीं पाएंगे,ताकि सोनिया जी के दिल को शांति मिल जाए।

राहुल अराजकता से खुद को सुर्खियों में रखते हैं : शाह ने कहा...राहुल जी चुनाव होते ही आप विदेश चले जाते हैं। देश में पसीना बहाना पड़ता है। हाथ में संविधान रखते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं करते। ईवीएम, एसआईआर,घुसपैठिए के मुद्दे पर हम संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं,चर्चा के लिए आ जाइए,लेकिन वे नहीं आएंगे। वे अराजकता से खुद को सुर्खियों में रखते हैं।

एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 52वें एयर फोर्स वाइस चीफ का पद संभाला

नई दिल्ली,02 नवम्बर 2026। नए वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित के कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 52वें वाइस चीफ का पद संभाल लिया है। फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए एयर मार्शल के पास अपने तीन दशकों से अधिक के करियर में मिग-21, मिग-23, मिग-27, जगुआर और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों पर 3200 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है।

उन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वालों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वायु सेना में 11 जून 1988 को फाइटर



स्ट्रीम में कमीशन हुए एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और वायु सेना अकादमी, डुंडीगुल के पूर्व छात्र हैं।

वह एडवांस्ड कमांड एंड स्टाफ कोर्स, यूनाइटेड किंगडम और नेशनल डिफेंस कॉलेज, बांग्लादेश के पूर्व छात्र भी हैं। उनके पास रक्षा और सामरिक अध्ययन में तीन स्नातकोत्तर डिग्री हैं।

विपक्ष जीतता है तो लोकतंत्र सुरक्षित,हारते ही आ जाता है खतरे में : नितिन नवीन

भागलपुर,02 नवम्बर 2026। बिहार के भागलपुर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान नितिन नवीन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उसके दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो उसे लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित नजर आता है, लेकिन जनता से चुनाव में हार मिलने के बाद वही लोकतंत्र को खतरे में बताने लगता है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने समय रहते अपनी मानसिकता नहीं बदली, तो आने वाले दिनों में जनता उसकी बची-खुची राजनीतिक जमीन भी छीन लेगी। इससे पहले सोमवार सुबह विशेष विमान से भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद लाजपत पार्क स्थित सभा स्थल और पदयात्रा मार्ग पर राजग कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी।



आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले तीनों विधायक बीजेपी में शामिल

बोले-पंजाब में फिरौती इंडस्ट्री बनी,गैंगस्टर सरकार में,तीनों ने पिछले दो दिन में इस्तीफा दिया

अमृतसर,02 नवम्बर 2026। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें अमृतसर नॉर्थ से कुंवर विजय प्रताप सिंह, समाना से चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर से हरमीत सिंह पठानमाजरा शामिल हैं। बीजेपी जॉइन करने के बाद विधायक कुंवर ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर सरकार का हिस्सा बन गए हैं। फिरौती की इंडस्ट्री चल रही है। इन तीनों विधायकों ने पिछले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। रविवार को जौड़ामाजरा और पठानमाजरा के इस्तीफे के बाद सोमवार को कुंवर ने भी पार्टी छोड़ दी। कुंवर और पठानमाजरा ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। कुंवर को जून 2025 में आम आदमी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था।



गैंगस्टर सरकार में,फिरौती इंडस्ट्री बनी : विधायक कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि पंजाब में जिन गैंगस्टरों के खिलाफ वह कोर्ट में गवाही दे रहे, वे सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। फिरौती एक इंडस्ट्री बन गई है। यह शर्मनाक है।

पंजाब को कर्ज में डुबोया : विधायक हरमीत पठानमाजरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने ढाई लाख करोड़ का कर्ज लिया। यह अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। जब मैंने पंजाब की बात उठाई तो मुझे परेशान किया गया।

संपादकीय

लोकतंत्र के लिए खतरा है भीड़तंत्र

आधुनिक राजनीतिक दर्शन में लोकतंत्र को केवल बहुमत का शासन नहीं,बल्कि संवाद,विमर्श और असहमति के सह-अस्तित्व की सतत प्रक्रिया माना जाता है। परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपनी वैधता और स्थायित्व तब प्राप्त करती हैं, जब नागरिकों को व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाने और शांतिपूर्ण प्रतिरोध का पर्याप्त अवसर मिलता है। असहमति को लोकतंत्र का सुरक्षा-वाल्व माना जाता है। इसके वैधानिक रास्ते बंद होने पर राजनीतिक व्यवस्था में अव्यवस्था की आशंका बढ़ जाती है। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्ण,सत्याग्रह-प्रेरित और कानून के दायरे में होने वाले जन आंदोलनों की जगह धीरे-धीरे आक्रामक,अनियंत्रित और व्यवस्था-विरोधी भीड़तंत्र लेता जा रहा है। जब असहमति सार्वजनिक जीवन को बाधित करने,राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रशासनिक तंत्र को बंधक बनाने का रूप लेती है,तब लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलने लगता है। कानूनों में संशोधन, विकास योजनाओं और संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में हुए प्रदर्शनों ने वैध जनविरोध और अराजक भीड़तंत्र के बीच अंतर निर्धारित करने का बुनियादी प्रश्न खड़ा कर दिया है। दक्षिण एशिया से पश्चिमी यूरोप तक की घटनाएं दर्शाती हैं कि जब जनांदोलन संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं,तो लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलने लगता है। वर्ष 2022 में श्रीलंका के अरगलाया आंदोलन और नेपाल में लगातार हुई नाकेबंदियों ने संस्थागत स्थिरता को कमजोर किया। वहीं अगस्त 2024 में बांग्लादेश का आरक्षण-विरोधी आंदोलन हिंसक सत्ता-परिवर्तन में बदल गया,जिसके बाद संसद,न्यायपालिका और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं गंभीर संकट में आ गईं। पश्चिमी लोकतंत्र भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। फ्रांस,इटली,बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन और अल्बानिया में लोग सरकारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस में महंगाई,शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और सार्वजनिक सेवाओं में कटौती के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन कुछ स्थानों पर आगजनी,लूटपाट और पुलिस के साथ झड़पों में बदल गए। इटली और बेल्जियम में भी प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई। परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इन देशों में वैधानिक प्रक्रियाओं के बजाय सड़क पर अराजकता के जरिये निर्णय हासिल करने की कोशिश चिंताजनक है। भारत के लिए भी यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ घरेलू तत्व इस अराजकता से कुप्रेरणा लेकर ढाका की तर्ज पर दिल्ली में रिजीम चेंज का आह्वान कर रहे हैं।

गहरे मतभेदों और लंबे आंदोलनों के बावजूद भारत तीन प्रमुख आधारों पर अपने पड़ोसी देशों (श्रीलंका,बांग्लादेश और नेपाल) की तरह संस्थागत पतन या तख्तापलट से बचा रहा है। पहला,पड़ोसी देशों से अलग भारतीय सेना पूरी तरह गैर-राजनीतिक रही है और उसने हमेशा निर्वाचित नागरिक सरकार तथा संविधान के अधीन अपनी भूमिका निभाई है। दूसरा,संघीय ढांचा और केंद्र तथा राज्यों में होने वाले नियमित चुनाव सुरक्षा वाल्व का काम करते हैं। इनके माध्यम से जनता का असंतोष सड़कों पर लंबे समय तक बने रहने के बजाय मतपेटियों के जरिये अभिव्यक्त होता है। तीसरा,सक्रिय न्यायपालिका ने कार्यपालिका और प्रदर्शनकारियों के बीच संवैधानिक मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। यही संस्थागत लचीलापन और संतुलन भारत को राजनीतिक अराजकता से बचाए रखने में मदद करता है। लोकतंत्र को भीड़तंत्र से बचाने और जनांदोलनों को संवैधानिक दायरे में रखने के लिए चार संस्थागत सुधार जरूरी हैं। पहला,पूर्व-विधायी परामर्श नीति,2014 को सख्ती से लागू करते हुए विधेयकों को कम से कम 30 दिनों तक सार्वजनिक विमर्श के लिए रखा जाए,ताकि नीतिगत असंतोष समय रहते दूर हो सके। दूसरा, प्रकाश सिंह वाद (2006) के निर्देशों के अनुरूप पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए और उसे आधुनिक,गैर-घातक भीड़-नियंत्रण तकनीकों तथा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण से लैस किया जाए। तीसरा, प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कठोर और पारदर्शी केंद्रीय कानून बनाया जाए। चौथा,हिंसा भड़काने वाले दुष्प्रचार पर अंकुश लगाने और एल्गोरिदम की जवाबदेही तय करने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की कानूनी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। पड़ोसी देशों और यूरोप में हुई हिंसक अशांति भारत के लिए गंभीर चेतावनी है। लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और नागरिकों को अपने संवैधानिक कर्तव्य निभाने चाहिए। सरकार का दायित्व है कि वह असहमति के स्वरों को संवेदनशीलता से सुने, वहीं प्रदर्शनकारियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर कानूनी और शांतिपूर्ण संवाद अपनाना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य जब तक एक-दूसरे के पूरक बने रहेंगे,तब तक भारत का लोकतंत्र भीड़ के क्षणिक उन्माद से अप्रभावित रहते हुए अपने संवैधानिक आदर्शों की रक्षा कर सकेगा।

विपक्षी हुंकार शक्ति-प्रदर्शन नहीं,जनकल्याण का कारण बने



ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन की व्यवस्था नहीं,बल्कि जनआकांक्षाओं, नागरिक अधिकारों,जवाबदेही और सार्थक राजनीतिक संवाद की जीवंत प्रणाली है। इसकी मजबूती केवल सत्तारूढ़ दल की कार्यक्षमता से नहीं,बल्कि विपक्ष की जिम्मेदारी, उसकी वैचारिक परिपक्वता और जनहित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से भी निर्धारित होती है। लेकिन जब विपक्ष की राजनीति का केंद्र जनता के बुनियादी सवालों के बजाय सत्ता का विरोध,नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमले और आरोपों की पुनरावृत्ति बन जाए,तब लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती को लेकर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग बीस विपक्षी दलों का जुटना और वोट चोरी के मुद्दे पर हुंकार भरना इसी संदर्भ में राजनीतिक समीक्षा की अपेक्षा करता है। सवाल यह नहीं कि विपक्ष को रैली करने का अधिकार है या नहीं, बल्कि यह है कि ऐसी रैलियों से लोकतंत्र और आम जनता को आखिर क्या हासिल हो रहा है?

रामलीला मैदान ऐतिहासिक रूप से जनआंदोलनों,राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिक प्रतिरोध का साक्षी रहा है। यहां उमड़ने वाली भीड़ को केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जा सकता,बल्कि उससे जुड़े संदेश और उद्देश्य का मूल्यांकन भी आवश्यक है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों को एक मंच पर लाकर अपनी राजनीतिक एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रयास किया। दस लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया था, लेकिन उपलब्ध विवरणों के अनुसार वास्तविक उपस्थिति इस दावे से काफी कम रही। फिर भी इस आयोजन का महत्त्व केवल भीड़ के आकार से नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक संदेश से तय होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इस रैली में भी विपक्ष की ओर से वही पुराने आरोप, वही राजनीतिक भाषण और वही सत्ता विरोधी तेवर अधिक दिखाई दिए, जिनकी पुनरावृत्ति लंबे समय से होती रही है।

वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का अधिकार ही नहीं,उसका दायित्व भी है। प्रत्येक वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहना चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आरोपों के साथ प्रमाण और तथ्यों की विश्वसनीयता भी आवश्यक है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रश्न उठाया जा रहा है, उनमें मृतक, स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता भी शामिल बताए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने भी एसआईआर से जुड़े निर्णयों को तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिया गया बताया है। इस प्रक्रिया को लेकर न्यायालय में विचार और निर्देश भी सामने आए हैं। इसलिए इस पूरे विषय पर अंतिम निष्कर्ष तथ्यों,प्रमाणों और न्यायिक परीक्षण के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। विपक्ष का दायित्व है कि वह चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग करे, मतदाता सूची की त्रुटियों को उजागर करे और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस प्रयास करे। लेकिन केवल वोट चोरी का नारा बुलंद करने से लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास मजबूत नहीं होगा। यदि विपक्ष वास्तव में मतदाता अधिकारों को लेकर गंभीर है तो उसे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने,मतदाता सूची की जांच करने,वास्तविक विसंगतियों के प्रमाण जुटाने और प्रभावित नागरिकों को न्याय दिलाने की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा नारों से कम और धरातल पर किए गए कार्यों से अधिक होती है। इस रैली का एक दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की राजनीतिक एकजुटता का आधार क्या है? क्या यह एकजुटता किसी साझा आर्थिक दृष्टि,रोजगार नीति,कृषि सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता,स्वास्थ्य सेवाओं, महंगाई,भ्रष्टाचार,महिला सुरक्षा,युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय के व्यापक कार्यक्रम पर आधारित है? अथवा इसका मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करना और सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक वातावरण तैयार करना है? यदि किसी गठबंधन की एकता का सबसे बड़ा आधार किसी एक नेता या सरकार का विरोध हो,तो उसकी वैचारिक स्थिरता और भविष्य की दिशा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सत्ता विरोध अपने आप में कोई राजनीतिक दर्शन नहीं हो सकता।



प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

लोकतंत्र में विपक्ष केवल आलोचक नहीं होता,वह वैकल्पिक नीतियों का निर्माता भी होता है। संसद में विधेयकों पर गंभीर चर्चा,सरकार की नीतियों का तथ्यात्मक परीक्षण,आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर वैकल्पिक सुझाव तथा जनता की आवाज को संस्थागत मंचों तक पहुंचाना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन जब राजनीतिक विमर्श आरोप-प्रत्यारोप,व्यक्तिगत कटाक्ष और विरोध प्रदर्शनों तक सीमित होने लगता है, तब जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। विपक्ष को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री की आलोचना करना और प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में अपनी योग्यता प्रमाणित करना दो अलग-अलग बातें हैं। पहली बात राजनीतिक विरोध है, जबकि दूसरी लोकतांत्रिक नेतृत्व की कसौटी है। आज भारत अनेक बुनियादी चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार,किसानों की आय और कृषि की उत्पादकता, छोटे व्यापारियों की आर्थिक सुरक्षा,शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार,पर्यावरण संरक्षण,शहरी अव्यवस्था,बढ़ती आर्थिक विषमता और महिलाओं की सुरक्षा जैसे प्रश्न किसी एक दल के नहीं,पूरे राष्ट्र के प्रश्न हैं। क्या रामलीला मैदान की हुंकार इन विषयों पर कोई ठोस वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकी? क्या विपक्ष ने यह बताया कि वह इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन-सी नीतियां अपनाएगा? क्या उसने देश के सामने कोई साझा विकास दृष्टि रखी? इन सवालों का उत्तर ही इस रैली की राजनीतिक सार्थकता का वास्तविक मूल्यांकन करेगा।

यह भी समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र में भीड़ जुटाना और जनमत अर्जित करना अलग-अलग बातें हैं। भीड़ किसी क्षणिक राजनीतिक उत्तेजना, संगठनात्मक शक्ति अथवा विरोध की भावना से जुट सकती है,लेकिन स्थायी जनविश्वास विचारों,नीतियों,आचरण और परिणामों से अर्जित होता है। राजनीतिक दलों को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि विशाल मंच,बड़े भाषण और एकजुटता के प्रदर्शन से जनता का विश्वास स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आज का मतदाता पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। वह केवल यह नहीं सुनना चाहता कि सरकार ने क्या गलत किया,बल्कि यह भी जानना चाहता है कि विपक्ष उस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करेगा। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होने के नाते उससे केवल विरोध की राजनीति नहीं,बल्कि वैचारिक नेतृत्व और रचनात्मक विपक्ष की अपेक्षा भी की जाती है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को अपनी राजनीतिक ऊर्जा का उपयोग ऐसे मुद्दों पर करना चाहिए,जो समाज के व्यापक वर्गों को प्रभावित करते हैं। विपक्षी एकता तभी सार्थक होगी, जब वह साझा नकारात्मकता के बजाय साझा सकारात्मक एजेंडे पर आधारित होगी। विभिन्न दलों के बीच नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के प्रश्नों पर सहमति बनाना आवश्यक है।

मोबाइल की दुनिया और बचपन का बिगड़ता व्यवहार

बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन से पहले संस्कार, संवाद और संवेदनशीलता देना जरूरी



डॉ.प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा



प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

पंचकूला के एक स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र द्वारा छह साल की बच्ची के साथ कथित क्रूर व्यवहार की खबर ने समाज को झकझोर दिया है। समाचार में सामने आए घटनाक्रम और विद्यालय परिसर में हुई हिंसा के विवरण ने बच्चों की सुरक्षा, उनके व्यवहार और हमारी परवरिश को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर बचपन में ऐसी हिंसक प्रवृत्तियाँ कैसे जन्म ले रही हैं? क्या बच्चों के भीतर संवेदनशीलता और सहानुभूति कम हो रही है? क्या मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट पर उपलब्ध हिंसक सामग्री और बदलते पारिवारिक वातावरण का उनके व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? इन सवालों से बचना अब संभव नहीं है। किसी एक घटना के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि बच्चों में बढ़ती हिंसा का कारण केवल मोबाइल फोन है। प्रत्येक घटना के पीछे व्यक्तिगत परिस्थितियाँ,पारिवारिक वातावरण,साथियों का प्रभाव,मानसिक स्थिति और सामाजिक परिवेश जैसे अनेक कारक हो सकते हैं। फिर भी यह सच है कि बच्चों के हाथों में पहुँच चुकी डिजिटल दुनिया ने माता-पिता की जिम्मेदारियों को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया है। अब बच्चों की निगरानी केवल स्कूल से लौटने के बाद उनके व्यवहार तक सीमित नहीं रह सकती। यह जानना भी आवश्यक है कि वे मोबाइल पर क्या देखते हैं, किन लोगों से बातचीत करते हैं,कौन-से खेल खेलते हैं और इंटरनेट से किस प्रकार के विचार ग्रहण कर रहे हैं। आज स्मार्टफोन बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई,शैक्षिक वीडियो और ज्ञानवर्धक सामग्री के माध्यम से तकनीक ने सीखने के नए अवसर खोले हैं। लेकिन इसी माध्यम पर हिंसक दृश्य,अपमानजनक भाषा,खतरनाक चुनौतियाँ और दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। समस्या तकनीक के अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित उपयोग,अनुचित सामग्री तक पहुँच और उसके प्रभावों को समझने की कमी में है। बच्चे कई बार मनोरंजन के नाम पर ऐसी सामग्री देखते हैं,जिसके परिणामों को समझने के लिए वे मानसिक और भावनात्मक रूप से पर्याप्त परिपक्व नहीं होते।

बचपन अनुकरण की अवस्था है। बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर भाषा,व्यवहार और प्रतिक्रिया करना सीखते हैं। वे माता-पिता की बातचीत, परिवार के सदस्यों के आचरण,मित्रों के व्यवहार और डिजिटल माध्यमों पर दिखाई देने वाली गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। यदि किसी बच्चे को बार-बार हिंसा, अपमान,बदले और आक्रामकता को सामान्य रूप में प्रस्तुत करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं,तो उसके व्यवहार पर उनका प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि हर बच्चा ऐसी सामग्री देखकर हिंसक नहीं बनता,लेकिन उम्र के अनुरूप सामग्री चुनना और उसके प्रभावों पर बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर व्यस्तता के कारण बच्चों को शांत रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। खाना खिलाने से लेकर उन्हें व्यस्त रखने तक,स्क्रीन एक आसान उपाय बन गई है। धीरे-धीरे यह आदत बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और अभिभावकों का ध्यान इस बात से हट जाता है कि बच्चा वास्तव में क्या देख रहा है। बच्चे का मोबाइल पर चुपचाप लगे रहना उसकी सुरक्षा या स्वस्थ विकास का प्रमाण नहीं है। डिजिटल दुनिया में उसकी गतिविधियों की जानकारी रखना, उम्र के अनुरूप सीमाएँ निर्धारित करना और उसके साथ नियमित संवाद बनाए रखना आवश्यक है। बच्चों पर नजर रखने का अर्थ उन पर हर समय संदेह करना या उनकी निजता को पूरी तरह समाप्त कर देना नहीं है। इसका अर्थ है उनकी सुरक्षा के प्रति सजग रहना और ऐसा विश्वासपूर्ण वातावरण बनाना, जिसमें वे अपनी परेशानी, जिज्ञासा और गलतियों के बारे में खुलकर बात कर सकें। माता-पिता को बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कौन-से खेल खेलते हैं, इंटरनेट पर क्या नया देखते हैं और किसी वीडियो या घटना के बारे में उनकी क्या समझ है। यदि बच्चा किसी हिंसक दृश्य को देखकर उत्साहित होता है, किसी को चोट पहुँचाने की बात करता है या उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आता है, तो उसे केवल डाँटकर चुप कराने के बजाय कारण समझने का प्रयास करना चाहिए।

विद्यालयों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना और परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना नहीं है। विद्यालय बच्चों को संवेदनशील, जिम्मेदार और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाने का भी माध्यम हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहार में आने वाले असामान्य बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में परामर्श व्यवस्था,भावनात्मक शिक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और दूसरों की गरिमा का सम्मान करने से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चों के बीच मारपीट, धमकी, अपमान या किसी कमजोर विद्यार्थी को निशाना बनाने की घटनाओं को सामान्य शरारत समझकर टालना भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही, किसी बच्चे द्वारा गंभीर गलती किए जाने पर उसके व्यवहार की जवाबदेही तय करना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है कि जाँच और कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हो। बच्चों को अपराधी घोषित करने की जल्दबाजी,सार्वजनिक अपमान या सोशल मीडिया पर उनकी पहचान उजागर करना उचित नहीं है। पीड़ित बच्चे की सुरक्षा,सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि किसी बच्चे के व्यवहार में हिंसा,असामान्य आक्रामकता या भावनात्मक संकट के संकेत दिखाई दें,तो अभिभावकों और विद्यालयों को योग्य बाल मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। डिजिटल मंचों और सरकार की भूमिका पर भी विचार करना होगा। बच्चों के लिए अनुचित सामग्री तक पहुँच रोकने,अभिभावकीय नियंत्रण के साधनों को सरल बनाने और आयु के अनुरूप डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इंटरनेट कंपनियों को भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन किसी तकनीकी सुविधा पर पूरी तरह निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल मोबाइल चलाना सीखना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज सही,सुरक्षित या अनुकरण करने योग्य नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को केवल नियमों से नहीं, उदाहरणों से भी सिखाया जाता है। यदि घर में गुस्से के समय अपशब्दों का प्रयोग होता है, विवादों का समाधान मारपीट से किया जाता है और दूसरों के प्रति अपमानजनक व्यवहार सामान्य माना जाता है, तो बच्चों से पूर्णतः विपरीत आचरण की अपेक्षा करना कठिन होगा। परिवार में संवाद, धैर्य, सहानुभूति और सम्मान का वातावरण बनाना होगा। बच्चों के साथ समय बिताना, उन्हें खेलकूद,पुस्तक-पठन,रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल के अवसर देना भी जरूरी है।

तथाकथित लोकतांत्रिक प्रदर्शन बनाम आर्थिक नुकसान



संजीव कुमार ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

लोकतंत्र का अर्थ केवल अपनी बात मनवाना नहीं,बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी है। सत्ता की कुर्सी स्थायी नहीं होती,राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन देश की अर्थ व्यवस्था और जनता की मेहनत से निर्मित संपत्ति पूरे राष्ट्र की धरोहर है। इसलिए अब समय आ गया है कि हर राजनीतिक प्रदर्शन के साथ आर्थिक जवाबदेही भी तय हो। क्योंकि देशहित से बड़ा न कोई दल है,न कोई नेता और न ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा। लोकतंत्र जनता का,जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इस व्यवस्था में अपनी बात मनवाने,असहमति जताने और सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार हर नागरिक और राजनीतिक दल को संविधान ने दिया है। अनुच्छेद-19 के तहत मिला शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हमारे लोकतंत्र की प्राण वायु है। किंतु,जब यही लोकतांत्रिक प्रदर्शन अनियंत्रित होकर चक्काजाम,तोड़फोड़,आगजनी और अनिश्चितकालीन अवरोधों में बदल जाते हैं,तब वे जनहित के बजाय राष्ट्रीय क्षति का पर्याय बन जाते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और विचारधारा को अपनी बात रखने, असहमति व्यक्त करने तथा सत्ता के सामने सवाल उठाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष,दोनों को अपनी राजनीतिक शक्ति और जनसमर्थन प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है। धरना, प्रदर्शन,रैली,जुलूस और शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वाभाविक अंग हैं। लेकिन जब यही लोकतांत्रिक अधिकार शक्ति प्रदर्शन,रास्ता रोकने,बाजार बंद कराने,सरकारी कामकाज बाधित करने और सार्वजनिक जीवन को अस्त-व्यस्त करने का माध्यम बन जाता है,तब एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस कथित लोकतांत्रिक गतिविधि की आर्थिक कीमत कौन चुकाएगा?

आज सवाल यह नहीं है कि विरोध करने का अधिकार है या नहीं,बल्कि बड़ा सवाल यह है कि इस तथाकथित लोकतांत्रिक प्रदर्शन के नाम पर देश को जो भारी-भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है,उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा? जब राजधानी या देश के किसी भी बड़े हिस्से में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़कों को महीनों या हफ्तों के लिए बंधक बना लिया जाता है,तब केवल प्रशासनिक व्यवस्था ही ध्वस्त नहीं होती,बल्कि देश की धड़कन यानी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा जाती है .व्यापार और खुदरा बाजार का संकटः त्यौहारों या पीक सीजन के दौरान होने वाले प्रदर्शन बाजारों की कमर तोड़ देते हैं। सरोजनी नगर,कनॉट प्लेस या देश के अन्य बड़े व्यावसायिक केंद्रों के दुकानदारों का करोड़ों का व्यापार ठप हो जाता है। खरीदार घरों में कैद रहने को मजबूर होते हैं,और छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों तथा दैनिक वेतन भोगियों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाता है। सड़कों के जाम होने से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार थम जाती है। समय पर माल न पहुंच पाने से उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होता है और वैश्विक स्तर पर देश की साख को तगड़ा झटका लगता है। प्रदूषण कार्यों को यह अंदाजा नहीं होता कि उनके कारण करोड़ों मानव-घंटों की बर्बादी होती है.एंबुलेंस में जूझते मरीज,समय पर दफ्तर या परीक्षा केंद्र न पहुंच पाने वाले युवा और ईंधन की बर्बादी यह वह अदृश्य नुकसान है जिसे कोई जीडीपी के आंकड़ों में सीधे तौर पर दर्ज नहीं करता,लेकिन देश का हर आम नागरिक इसे रोज भोगता है।दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज विरोध प्रदर्शन जनहित से ज्यादा राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता के समीकरणों को साधने का जरिया बन चुके हैं। सत्ता में बैठी पार्टी हो या विपक्ष, दोनों के लिए आंदोलन एक ऐसा हथियार बन गया है जहाँ देश के आर्थिक नुकसान की कीमत पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी आसान लगती है। जब विपक्ष सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश करता है,तो आम जनजीवन दांव पर लग जाता है। इसके विपरीत, सत्ता पक्ष अक्सर इन अवरोधों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखता है, और समस्या के मूल समाधान के बजाय इसे एक-दूसरे पर छींटाकशी का माध्यम बना लेता है।



प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

इस संदर्भ में,हाल ही में मुख्यधारा के राजनेताओं के विरोधाभासी वक्तव्य भी सामने आए हैं। सत्ता पक्ष जहाँ इन प्रदर्शनों को अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी और प्रायोजित अराजकता करार देता है,वहीं विपक्ष के प्रमुख नेता जैसे लोकसभा में विपक्ष के अनेक राजनेता भी रैलियों और प्रदर्शनों के बीच जनता को यह सलाह देते नजर आते हैं कि प्रदर्शन भी करो और साथ में छोटे दुकानदारों से खरीदारी भी करो ताकि व्यापारियों का नुकसान न हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या महज़ रैलियों के बीच थोड़ी-बहुत खरीदारी करने की अपील से उन करोड़ों के नुकसान की भरपाई हो सकती है, जो सप्लाई चेन टूटने, ट्रैफिक ठप्प होने और अनिश्चितकालीन बंदी से उद्योगों व खुदरा बाजार को झेलना पड़ता है? राजनीतिक मंचों से दिए जाने वाले ये बयान महज बयानबाजी बनकर रह जाते हैं,जबकि यथार्थ के धरातल पर नुकसान का बोझ सिर्फ और सिर्फ आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था उठाती है।इस विकट स्थिति से उबरने के लिए अब केवल नैतिक उपदेशों से काम नहीं चलेगा,बल्कि कड़े और स्पष्ट प्रशासनिक तथा कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर केवल अज्ञात भीड़ पर केस दर्ज करने के बजाय प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों और राजनीतिक दलों के नेताओं को आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नुकसान का आकलन कर उसकी वसूली सीधे उन दलों या संगठनों की संपत्तियों से होनी चाहिए जिन्होंने आन्दोलन का आह्वान किया थाद्य न्यायपालिका को अब ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए संवैधानिक टॉर्ट के सिद्धांतों के तहत उन लोगों को मुआवजा दिलाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए,जिनका व्यापार,समय और अधिकार इन मनमाने अवरोधों की भेंट चढ़ जाता ह दुनिया के कई विकसित देशों की तरह भारत में भी विरोध प्रदर्शनों के लिए शहरों से बाहर या निश्चित प्रजातांत्रिक स्थल तय होने चाहिए,जहाँ आम जनता का जनजीवन, ट्रैफिक और अर्थव्यवस्था बाधित हुए बिना लोग अपनी आवाज बुलंद कर सकें। लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए,किंतु असंतोष व्यक्त करने के अधिकार की कोई ऐसी कीमत नहीं होनी चाहिए, जिसे पूरा देश चुकाने के लिए विवश हो जाए। सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने या वहां टिके रहने की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं देश की आर्थिक प्रगति के पहिये को जाम करने का लाइसेंस नहीं बन सकतीं। जब तक प्रदर्शनकारियों और उनके आकाओं को यह अहसास नहीं कराया जाएगा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलने की एक भारी आर्थिक कीमत चुकानी होगी,तब तक देश की प्रगति यूं ही बाधित होती रहेगी। अब समय आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में एक कठोर राष्ट्रीय नीति बनाई जाए,जो अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य और उत्तरदायित्व को भी उतनी ही दृढ़ता से लागू करे।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

एक अफसाना

बुढ़ापे की लाचारी और कमज़ोर होते जिस्म ने उनकी हिम्मत को और तोड़ दिया था..

शाम का वक्त था। बाहर हल्की-हल्की फुहार पड़ रही थी और लिविंग रूम में दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक के अलावा पूरे घर में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था।

कभी इस घर में मास्टर दीवान चंद की धाक हुआ करती थी। उनके घर में क़दम रखते ही बेटा आलोक चुपचाप अपनी किताबों में सिर गड़ा देता था। वह दौर दूसर

विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा छत्तीसगढ़...किसानों-आदिवासियों और महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता : रामविचार नेताम

राज्योत्सव में कृषि मंत्री ने गिनाईं 26 वर्षों की उपलब्धियां,कहा...छत्तीसगढ़ को विकास का सशक्त मॉडल बनाने सरकार प्रतिबद्ध







आरु साहू के छत्तीसगढ़ी गीतों ने बांधा समां,स्वप्निल जायसवाल सहित स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों से देर शाम तक झूमता रहा कला केंद्र मैदान

विभिन्न विभागों के स्टॉल बने आकर्षण, शासन की योजनाओं की दी गई जानकारी; अनेक हितग्राहियों को सामग्री, चेक, प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र वितरित







-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमवार को अम्बिकापुर के कला केंद्र मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव-2026 का भव्य एवं रंगारंग आयोजन किया गया। उत्साह,उमंग और सांस्कृतिक उल्लास के बीच आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास के एक सशक्त मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। प्रदेश का वास्तविक विकास किसानों,आदिवासियों, युवाओं,महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से ही संभव है। उन्होंने राज्य निर्माण के 26 वर्षों को गौरवशाली यात्रा बताते हुए प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच और ऐतिहासिक निर्णय का परिणाम है। राज्य गठन के बाद से प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है और आज नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार सड़क,बिजली, पेयजल,स्वास्थ्य,आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। गांव-गांव तक पक्की सड़क, आवास और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि,समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना और स्वाइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए नए धान खरीदी केंद्र भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि राज्योत्सव केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं,बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य के प्रति सामूहिक संकल्प को दोहराने का भी अवसर है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर,जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह,नगर निगम अम्बिकापुर की महापौर मंजूषा भगत,सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव ने भी जिलेवासियों को राज्योत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में कलेक्टर अजीत वसंत,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल,जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव,अपर कलेक्टर प्रताप विजय खेस्स, नगर निगम आयुक्त विनय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि,अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

सरगुजा सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : प्रबोध मिंज

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने राज्य निर्माण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 26 वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार सरगुजा संभाग सहित पूरे प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से विकास की नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

हितग्राहियों को मिली योजनाओं की सौगात, मंत्री ने वितरित की सामग्री एवं प्रमाण पत्र : राज्योत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि रामविचार नेताम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री,चेक,प्रमाण-पत्र एवं नियुक्ति पत्र वितरित किए। पशुधन विकास विभाग की नर बकरा योजना के तहत दो हितग्राहियों को चेक प्रदान किए गए। कृषि विभाग ने पांच किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड तथा मत्स्य पालन विभाग ने एक हितग्राही को आइस बॉक्स एवं जाल वितरित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से हब के तीन तथा सखी निवास के दो हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तीन हितग्राहियों को खुशियों की चाबी सौंपी गई। बिहान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 11 स्व-सहायता समूहों को चेक तथा दो समूहों को सीएलएफ संचालन के लिए महतारी सदन की चाबी प्रदान की गई। इसी प्रकार पर्यटन विभाग के तीन तथा जेल विभाग के दो हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के माध्यम से एक हितग्राही को जाति प्रमाण-पत्र तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दो हितग्राहियों को सहायक उपकरण दिए गए। समाज कल्याण विभाग ने पांच हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की।

आरु साहू के गीतों पर झूमे दर्शक, स्थानीय कलाकारों ने बिखेरी सांस्कृतिक छटा : राज्योत्सव की शाम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के नाम रही। आमंत्रित कलाकारों, विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं तथा स्थानीय प्रतिभाओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समारोह को यादगार बना दिया। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय गायिका आरु साहू ने अपने छत्तीसगढ़ी गीतों से ऐसा समां बांधा कि दर्शक देर शाम तक कार्यक्रम स्थल पर जमे रहे। वहीं स्थानीय गायक स्वप्निल जायसवाल ने बॉलीवुड गीतों की प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। स्थानीय कलाकारों में मुकुल विश्वास, कल्पना गुप्ता, सीमा तिवारी, अमित श्रीवास्तव, पल्लवी एवं पलक पाण्डेय, प्रियांशु मिश्रा, हिमांगी त्रिपाठी और अस्मि वर्मा ने गायन की प्रस्तुतियां दीं। वहीं सिमरन प्रधान,सभ्या शर्मा,अक्षिता डबराल,सृष्टि भदौरिया,रघुवंश कुमार एवं आश्वी तिवारी ने नृत्य के माध्यम से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। कन्या शिक्षा परिसर अम्बिकापुर,संगीत महाविद्यालय अम्बिकापुर,कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने सामूहिक नृत्य एवं आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलने से समारोह में क्षेत्रीय कला एवं संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिली।

विभागीय स्टॉलों में दिखी योजनाओं की झलक,रजवार भित्ति कला और तिब्बती स्टॉल भी आकर्षण

राज्योत्सव स्थल पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहान,जनसंपर्क,स्कूल शिक्षा, पर्यटन,वन,समाज कल्याण, उद्यानिकी, कृषि, पशु चिकित्सा,मत्स्य पालन,नगर निगम, आदिवासी विकास,महिला एवं बाल विकास, सरगुजा पुलिस,केंद्रीय जेल तथा राजस्व विभाग के स्टॉलों में लोगों ने रुचि दिखाई। इसके अलावा तिब्बती स्टॉल और रजवार भित्ति कला की प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विभागीय योजनाओं की जानकारी, उपलब्धियों के प्रदर्शन और स्थानीय कला-संस्कृति की झलक के साथ अम्बिकापुर का जिला स्तरीय राज्योत्सव उत्सव, उपलब्धियों और विकास के संकल्प का साझा मंच बनकर सामने आया।

पटवारियों की हड़ताल से अटके किसानों के काम धान खरीदी से पहले प्रशासन की बढ़ी चिंता...

डिजिटल क्रॉप सर्वे,फसल क्षति आकलन और राजस्व प्रकरण प्रभावित,संभाग के 819 पटवारियों को काम पर लौटने का निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले पटवारियों की हड़ताल ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक, किसानों के अभिलेखों का सत्यापन और चक्रवाती तूफान से फसल क्षति के आकलन जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण भी प्रभावित हो रहा है। स्थिति को देखते हुए संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने सरगुजा संभाग के सभी छह जिलों के 819 हड़ताली पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त ने सभी एसडीएम को आंदोलनरत पटवारियों को नोटिस जारी कर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने और संबंधित तहसीलदार के माध्यम से उसी दिन व्यक्तिगत लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। संभाग में सूरजपुर के 192, सरगुजा के 216, कोरिया के 60, एमसीबी के 51, जशपुर के 150 और बलरामपुर के 150 पटवारी हड़ताल पर हैं। बलरामपुर जिले में मुख्यालय में निवास नहीं करने पर पांच पटवारियों को निलंबित भी किया गया है।



नोटिस जलाकर जताया विरोध

इधर, प्रशासन की सख्ती के विरोध में सरगुजा जिले के पटवारियों ने सोमवार को धरनास्थल पर नारेबाजी करते हुए कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाईं। पटवारी अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। राजस्व पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने कहा कि संविधान ने सभी को अपनी मांगें रखने का अधिकार दिया है। शासन दमनात्मक कार्रवाई कर आंदोलन खत्म कराने का प्रयास कर रहा है, जो गलत है। वहीं, डिम्पल गुप्ता ने कहा कि पदोन्नति सबका अधिकार है और वे इसे लेकर रहेंगे।

अनुपस्थिति पर ब्रेक इन सर्विस की चेतावनी

संभागायुक्त ने कहा कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति या स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहने से समयबद्ध शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। चक्रवाती तूफान से फसल क्षति का सर्वेक्षण कर किसानों को पात्रतानुसार राहत देने की कार्रवाई भी प्राथमिकता से की जानी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थिति अवधि के वेतन और अन्य सेवा लाभों पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा तथा इस अवधि को सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा।



21 साल से कमीशन वृद्धि नहीं,राशन दुकान संचालकों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

लंबित भुगतान और क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर आंदोलन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक एवं विक्रेता कल्याण संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। संघ का कहना है कि लंबे समय से कमीशन में वृद्धि नहीं होने और वित्तीय सहायता की राशि लंबित रहने से दुकान संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।

संघ की प्रमुख मांगों में पिछले 21 वर्षों से स्थिर कमीशन दर में वृद्धि करना शामिल है। संचालकों ने सीजीएफएसए मद के चावल, शक्कर, चना, रिफाइंड अमृत नमक वितरण पर केंद्र सरकार के समान कमीशन देने की मांग की है। इसके अलावा भंडारण एवं वितरण के दौरान राशन में होने वाली कमी की भरपाई के लिए 2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने की मांग रखी गई है।

संघ ने जुलाई 2016 से संचालित वित्तीय सहायता व्यवस्था के तहत वर्ष 2023 के बाद से लंबित भुगतान तत्काल जारी करने की मांग भी की है। वहीं, जिला स्तर पर 2 प्रतिशत टीडीएस कटौती बंद करने और बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य दुकान संचालकों की लंबित स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर केवल आश्वासन मिलने से संचालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर प्रदेशभर के उचित मूल्य दुकान संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने को बाध्य होंगे।

पिकअप पेड़ से टकराया,चालक की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुई पिकअप वाहन पेड़ से टकरा गई। हादसे में घायल चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के ग्राम शारदापुर चकिमा का बिजेन्द्र पिता स्व. घासीलाल 40 वर्ष, 31 अक्टूबर को पिकअप वाहन से मैनपाट आलू लेने के लिए अपने सहयोगी आकाश के साथ गया था। आलू लोड करके वापस लौटते वक्त ढलान में वह धीरे-धीरे पिकअप वाहन को उतारने की बात कहते हुए आकाश को नीचे उतर जाने के लिए कहा। ढलान में कुछ दूर जाने के बाद पिकअप का ब्रेक फेल हो गया और अनियंत्रित वाहन पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आननफानन में वाहन में फंसे चालक बिजेन्द्र में मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लाया गया, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

मृतकों के आत्मा की शांति के लिए कब्रिस्तान में विशेष पूजा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

रोमन कैथोलिक समुदाय द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 नवंबर को मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कब्रिस्तान में विशेष पूजा समारोह का आयोजन किया गया। समुदाय के लोगों ने अपने मृत परिजनों और पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की, साथ ही चालू वर्ष में स्वर्गवासी हुए सदस्यों (पचबालार) की संगति में मिलने का रस्म भी अदा किया गया। समुदाय की मान्यता के अनुसार पूर्वजों की आत्माएं जीवित वंश के अपने लोगों को सुरक्षा देने एवं विकास के मार्ग में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशप डॉ. अनोनीस बड़ा की अध्यक्षता में हुए समारोह दौरान अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मृत्यु की घटना से एक सामान्य व्यक्ति भय खाता है, किंतु यह प्रक्रिया अनंत जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक है। हम आज यहां अपने पूर्वजों की आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करने और स्वयं के अनंत जीवन में प्रवेश की अच्छी तैयारी के लिए विशेष प्रार्थना करने आए हैं। समारोह के सह-अनुष्ठाताओं में फादर ग्रेगोरी, अलेक्स एक्का, अजय बरवा, ज्ञान प्रकाश और प्रदीप एक्का शामिल थे। समुदाय के प्रमुख लोगों में फ्रांसिस कस्केट्टा, जगजीत मिंज, राजेन्द्र तिग्गा, जोसेफ किण्डो, डेविड एक्का, फिरमा, मंजेरेल्ला लकड़ा सहित हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे।





मानव की मृत्यु के बाद की कैथोलिक मान्यता

इस अवसर पर मानव की मृत्यु के बाद की स्थिति पर कैथोलिक मान्यता के बारे में भी बताया गया। विश्वास के सिद्धांत अनुसार मनुष्य की सृष्टि ईश्वर के सान्निध्य प्राप्ति के लिए हुई है, लेकिन मानव पर कोई दबाव नहीं है कि वह नियत बर्ताव ही करे। अतः मृत्यु के पश्चात मनुष्य के कर्म के अनुसार उसकी आत्मा को फल प्राप्त होता है। मुख्य बात यह है कि एक दिन संसार का अंत आएगा और सभी मृतकों को पुनर्जीवन मिलेगा और अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्ति होगी।

'सशक्त नारी,युवा उड़ान' की थीम पर सजा राज्योत्सव, मंच से स्टॉल तक दिखी बदलते बलरामपुर की तस्वीर

26 वर्षों की विकास यात्रा का उत्सवः बलरामपुर राज्योत्सव में योजनाओं की प्रदर्शनी और लोकनृत्यों की धूम













हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ,स्टॉलों में दिखी योजनाओं की झलक, मंच पर बिखरे लोकसांस्कृति के रंग

सुवा से शिव तांडव तक,लोक मंथन से अक्षत कलेक्टिव तक : राज्योत्सव की सांस्कृतिक संध्या में झूम उठा बलरामपुर

-संवाददाता-
बलरामपुर,02 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर हाई स्कूल मैदान, बलरामपुर में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव में एक ओर मंच पर लोकरंगों की छटा बिखरी,तो दूसरी ओर विभागीय स्टॉलों में शासन की योजनाओं से बदलते जिले की तस्वीर साकार दिखी। श्सशक्त नारी,युवा उड़ान थीम पर आधारित इस आयोजन में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।



सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, जनपद पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर सुश्री सुमित्रा चेरवा तथा नगर पालिका अध्यक्ष श्री लोधीराम एक्का,जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित जनप्रतिनिधि,अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने छत्तीसगढ़ी में जय जोहार कहते हुए उपस्थित जनसमूह से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रिय छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 26 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है और इस वर्ष का उत्सव श्सशक्त नारी, युवा उड़ानश् थीम पर आधारित है। बेटियों के विद्यालय का यह मैदान स्वयं इस थीम का सबसे सुंदर प्रतीक है, क्योंकि यहाँ से पढ़कर निकलने वाली बेटियाँ ही कल के छत्तीसगढ़ की दिशा तय करेंगी। उन्होंने कहा कि कभी खनिज प्रदेश कहलाने वाला छत्तीसगढ़ आज औद्योगिक राज्य बन रहा है और अंबिकापुर के माँ महामाया हवाई अड्डे से सरगुजा के लोग दिल्ली, कोलकाता,रायपुर और बिलासपुर तक उड़ान भर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनेक घर बहनों के नाम पर बने हैं,उज्ज्वला ने रसोई से धुआँ दूर किया है और महतारी वंदन योजना से बहनों के हाथ में सीधी आर्थिक सहायता पहुँच रही है। धरती आबा अभियान और पीएम-जनमन से आदिवासी बस्तियों तक सड़क, आवास,पानी और बिजली पहुँच रही है। बेटियों से बड़े सपने देखने और युवाओं से नौकरी देने वाला बनने का आह्वान करते हुए उन्होंने नागरिकों से अपील की कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह सबकी साझा जिम्मेदारी है। सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा ने भी जिलेवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएँ दीं। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने स्वागत उद्बोधन में राज्योत्सव की थीम को पेड़ के उदाहरण से समझाते हुए कहा कि जिले की जड़ों को मजबूत कर रही हैं हमारी दीदियाँ। जिले में 10 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों से लगभग 1 लाख 15 हजार परिवार जुड़े हैं और छोटी बचत से शुरू हुआ उनका सफर लखपति दीदी तक पहुँच रहा है। उन्होंने बताया कि प्रिज्मा एआई के साथ हुए समझौते के बाद बलरामपुर एआई डेटा एनोटेशन सेंटर स्थापित करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है, जहाँ दीदियाँ और युवा अपने जिले में रहकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम सीखेंगे। मिशन आचार्य से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जा रही है और श्बालभोगश् के तहत रागी व मिलेट्स से बना पौष्टिक लड्डू आकांक्षी विकासखंड शंकरगढ़ के 967 बच्चों को प्रतिदिन दिया जा रहा है। उन्होंने चांगरो के जैविक जीराफूल चावल की ब्रांडिंग तथा जल संरक्षण के लिए किसानों द्वारा स्वेच्छा से अपनी भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा देने वाले 5 प्रतिशत मॉडल का उल्लेख करते हुए इसे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की परंपरा का विस्तार बताया।

कलेक्टर ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहीमूलक सामग्री प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से पूजा मण्डल, आर्यन रवि और अनिकेत तिर्की को व्हील चेयर, प्रमोद कोड़ाकू को दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन के तहत 50 हजार रुपये तथा महेन्द्र कांसी को दिव्यांगजन उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 6 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। वन विभाग ने हाथी से जनहानि के प्रकरण में 6 लाख रुपये और मकान क्षति के प्रकरण में 25 हजार रुपये का क्षतिपूर्ति चेक सौंपा। स्वामित्व योजना के तहत ग्राम भनौरा के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के विद्यालयों और छात्रावासों के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी स्वागत नृत्य,सुवा नृत्य,छत्तीसगढ़ी रिमिक्स, शिव तांडव,कान्हा नृत्य,सूफी नृत्य तथा घूमर, हरियाणवी,अरुणाचली और नेपाली लोकनृत्यों सहित अन्य प्रस्तुतियाँ दीं। भेलवाडीह के पहाड़ी कोरवा कलाकारों का उड़िया लोकनृत्य और नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब तालियाँ बटोरीं। कार्यक्रम में कसडोल के लोक मंथन दल ने जनजातीय नृत्य से वनांचल की परंपरा को मंच पर जीवंत किया,बिलासपुर की वाइब्रेशन डांस एकेडमी के कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकनृत्य प्रस्तुत किए तथा बनारस के अक्षत कलेक्टिव ने उप-शास्त्रीय एवं सुगम गायन से सुरों की महफिल सजाई।

राज्योत्सव में 22 विभागों के स्टॉलों में दिखी शासन की विकास और उपलब्धियों की झलक

जनकल्याणकारी योजनाओं,नवाचारों एवं विकास कार्यों से रूबरू हुए आमजन

-संवाददाता-
सूरजपुर,02 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य के 26 वाँ स्थापना दिवस के अवसर पर सशक्त नारी, युवा उड़ान की थीम पर अग्रसेन ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं,विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राज्योत्सव में जिले के 22 विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं एवं विभागीय उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर आम नागरिकों ने विभागीय प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शित योजनाओं, उपलब्धियों एवं नवाचारों की जानकारी ली । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं महिला सशक्तीकरण पर आधारित मॉडल और उत्पाद प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विकसित भारत ग्राम योजना के तहत वर्षा जल संचयन का जीवंत मॉडल, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पक्के आवास का मॉडल तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस गांव एवं अपशिष्ट प्रबंधन की झलक प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित रागी आटा, मक्का आटा,दाल,बेसन,मूंगफली सहित पारंपरिक खाद्य उत्पादों एवं हस्तनिर्मित चूड़ियों का प्रदर्शन किया गया।

उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी उत्पादों से महिला सशक्तिकरण, युवा आकांक्षाओं एवं प्रगति की उड़ान के प्रतीक के रूप में एयरोप्लेन का आकर्षक मॉडल तैयार किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के 26 वें स्थापना दिवस एवं विकास की गौरवशाली यात्रा को प्रज्वलित एवं मुस्कुराते दीपक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पोषण वाटिका,पोषण आहार की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पोषण आहार के महत्व को विस्तारपूर्वक बताया। प्रदर्शनी में बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर आहार की जानकारी दी गई। विभागीय स्टॉल में बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराध के दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया। शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के स्टॉल में नारी सशक्तिकरण एवं युवा उड़ान के थीम पर आधारित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। जिले के 1163 प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 49 हजार विद्यार्थियों को शब्दबीज नवाचार के तहत प्रतिदिन 10 मिनट में एक नया द्विभाषीय हिन्दी-अंग्रेजी शब्द उच्चारण एवं अर्थ सहित सिखाया जा रहा है। कक्षावार तैयार शब्दबीज पुस्तिका में प्रत्येक स्तर के लिए 150 शब्द निर्धारित किया गया है। इस पहल से बच्चों में सुनने,बोलने,पढ़ने एवं लिखने के कौशल के साथ शब्द भंडार का विकास हो रहा है,जिससे गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। आदिवासी विभाग में समाज की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करने वाला संस्कृति पारंपरिक वाद्य यंत्र,सहित अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। देवगुड़ी जनजातीय व्यंजन, एवं वाद्य यंत्रों में झेला मंजीरा जैसे यंत्रों की प्रदर्शनी ने दर्शकों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ दिया। जिला कौशल विकास विभाग द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,









प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना,मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना,आवेदन की प्रक्रिया, आदि के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के मॉडल प्रदर्शित किया गया है, जिनके माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और आधुनिक सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। स्टॉल में उपस्थित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निःशुल्क जांच एवं निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान की जानकारी साझा की गई है कृषि एवं उद्यानिकी विभागीय योजनाओं का प्रदर्शन के साथ ही दलहन, तिलहन, धान बीज एवं विभिन्न उद्यानिकी फसलों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में किसानों को उन्नत कृषि तकनीक,मशीन, फसल विविधीकरण की जानकारी दी गई। मछली विभाग द्वारा केंद्र पोषित योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पशुधन विभाग में गोधाम योजना,दवाइयां,वन विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं, विविध औषधि जड़ी बूटी का प्रदर्शन किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विधिक जागरूकता, सुरक्षित बचपन अभियान, स्पेशल लोक अदालत,नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। जल संसाधन विभाग द्वारा जल शक्ति अभियान अंतर्गत कनकपुर जलाशय योजना की प्रदर्शनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भटगांव , विश्रामपुर द्वारा कोल माइनिंग, श्रम विभाग द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना,मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना,मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। पुलिस विभाग के स्टॉल में यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। स्टॉल में प्रदर्शित पोस्टर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने,नशे में वाहन न चलाने जैसे संदेश दिया गया। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के लिए सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने जैसी उपयोगी सलाह भी दी गई। बिजली विभाग द्वारा पीएम सूर्य घर की प्रक्रिया को दर्शाने वाला उपकेंद्र का मॉडल प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल के माध्यम से आगंतुकों को यह बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई कि नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर स्वयं बिजली उत्पादक बन सकते हैं।

नशे में धुत युवकों ने स्कॉर्पियो से तीन बाइक को रौंदा,एक की मौत

तेज रफ्तार वाहन ने मचाया तांडव,हादसे के बाद स्कॉर्पियो पलटी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

उदयपुर थाना क्षेत्र में रविवार की शाम नशे में धुत युवकों ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से सड़क किनारे खड़ी तीन बाइक को टक्कर मारकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अंबिकापुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां ग्राम दावा निवासी राहुल यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परोगिया निवासी घरभरन यादव अपनी बहन की विदाई कराने के लिए गांव के राजमंत्री नामक



व्यक्ति की स्कॉर्पियो (सीजी 15 डीई 3846) बुक कराकर ग्राम बिनिया गया था। वहां उसकी मुलाकात राहुल, घरभरन और सनी से हुई। बताया जा रहा है कि तीनों शराब के नशे में थे। इस दौरान ससुराल पक्ष ने बहन की विदाई करने से मना कर दिया, जिसके बाद तीनों का अपने जीजा से विवाद हो गया। मामला कुन्नी चौकी पहुंचा। पुलिस ने समझाइश देकर शाम करीब सात बजे उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद तीनों युवक लखनपुर पहुंचे और वहां फिर शराब का सेवन किया। इसके बाद वे स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार से उदयपुर की ओर ले जाने लगे। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर खड़ी तीन बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो रामगढ़ रोड से लक्ष्मणगढ़ मार्ग की ओर भागी, लेकिन सानीबर्रा के झेरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0/..../अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती पूनम गुप्ता आ0 / पति दिनेश कुमार गुप्ता जाति निवासी महामाया रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - बरेजपारा, शीट नम्बर -8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2602/129 रकबा 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11.11.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः 26.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0/..../अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती पूनम गुप्ता आ0 / पति दिनेश कुमार गुप्ता जाति निवासी महामाया रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - बरेजपारा, शीट नम्बर -8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2602/35 रकबा 0.04 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11.11.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः 26.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

कार्यालय विशेष विवाह अधिकारी अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ0ग0)

वि.प्र.क. / विशेष विवाह / 2026 26

फार्म ''अ''

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह सार्वजनिक सूचना जारी किया जाता है कि आवेदक अविलास आ0 विष्णु,आयु 33 वर्ष,निवासी छोटा बाजार,पोस्ट थाना तहसील चिरमिरी, जिला एम0सी0बी0 छ0ग0 एवं आवेदिका लक्ष्मी एक्का आ0 कमल साय,उम्र 30 वर्ष,निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर बंजारी,पोस्ट अम्बिकापुर, थाना मणीपुर,तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा,छ0ग0, के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत आयशित विवाह / विवाह पंजीयन की सूचना संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रस्तावित अभिप्रेत विवाह पंजीयन की सूचना के विरूद्ध आपत्ति करने के इच्छुक कोई व्यक्ति इस न्यायालय में दिनांक 30/11/2020 को दिन के 11:00 बजे तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

सील — विशेष विवाह अधिकारी, अधिकापुर सरगुजा(छ0ग0)

CMYK



आरक्षण के बाद मतदाता सूची में वार्ड बदलने का खेल?

बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा में शिकायत से मचा हड़कंप

किस वार्ड में किसका नाम? मतदाता सूची पर कांग्रेस की शिकायत,निर्वाचन कार्यालय ने जांच का दिया निर्देश

वार्ड आरक्षण के बाद मतदाताओं के नामों में कथित फेरबदल,नगरीय चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल

गलत वार्डों में नाम दर्ज कराने और मतदाताओं के स्थानांतरण के लगाए आरोप, शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जांच का दिया निर्देश

जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग

मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत,10 नवंबर तक दावा-आपत्ति बढ़ाने की मांग, प्रशासन ने मांगी जांच रिपोर्ट

अब जांच की निष्पक्षता पर टिकी नजरें

- रवि सिंह-

बैकुंठपुर,02 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के दो नगरीय निकायों–बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा–में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच प्रारंभिक मतदाता सूची को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने मतदाता सूची के प्रकाशन और दावा-आपत्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की आशंका जताते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपी है, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वार्डों का आरक्षण घोषित होने के बाद कुछ मतदाताओं के नाम उनकी वास्तविक निवास वाली वार्ड सीमा के बजाय दूसरे वार्डों में दर्ज किए जा रहे हैं,कुछ मतदाताओं के नाम कथित तौर पर मनमाने ढंग से पसंदीदा वार्डों में स्थानांतरित कराने का दबाव बनाए जाने की शिकायत भी की गई है,यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में वार्डवार मतदाता सूची और आरक्षण की स्थिति का सीधा संबंध चुनावी प्रक्रिया से है,यदि मतदाताओं के नाम निर्धारित वार्डों के बजाय दूसरे वार्डों में दर्ज किए जाते हैं या नियमों के विपरीत स्थानांतरण होता है, तो इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो सकते हैं,ऐसे में शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच और प्रत्येक विवादित नाम का भौतिक सत्यापन आवश्यक हो गया है।

आरक्षण के बाद वार्डों में नाम बदलने के आरोप

जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने 30 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर को दिए गए शिकायत पत्र में कहा है कि बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा की प्रारंभिक मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं,शिकायत के अनुसार, निर्धारित वार्ड सीमाओं के अनुरूप नाम दर्ज होने के बजाय बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दूसरे और दूरस्थ वार्डों में दर्ज होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं,शिकायतकर्ता ने यह आशंका भी जताई है कि कुछ मतदाताओं के नाम जानबूझकर दूसरे वार्डों में जोड़ने तथा कुछ नामों को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाए जाने की जानकारी मिली है,इसके अलावा, चुनिंदा मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से पसंदीदा वार्डों में स्थानांतरित कराने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, यदि इन शिकायतों की पुष्टि होती है तो यह केवल मतदाता सूची की सामान्य त्रुटि नहीं होगी,बल्कि मतदाताओं के वार्ड निर्धारण और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा गंभीर मामला बन सकता है, हालांकि, अभी ये शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं,इनकी पुष्टि जांच और संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही हो सकेगी।

वार्ड आरक्षण के बाद नामों के स्थानांतरण का आरोप क्यों गंभीर?

नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों का आरक्षण घोषित होने के बाद प्रत्येक वार्ड की राजनीतिक और चुनावी परिस्थितियां बदल जाती हैं, ऐसे में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए,शिकायत में इसी बिंदु को प्रमुखता से उठाया गया है,आरोप है कि वार्डों की निर्धारित सीमाओं के अनुसार नाम दर्ज करने के बजाय कुछ मतदाताओं को दूसरे वार्डों में स्थानांतरित करने की शिकायतें सामने आ रही हैं,यदि किसी मतदाता का नाम वास्तविक निवास स्थान से अलग वार्ड में दर्ज होता है तो उसे अपने मताधिकार के प्रयोग में परेशानी हो सकती है, वहीं,यदि ऐसा बदलाव जानबूझकर और किसी चुनावी लाभ के उद्देश्य से किया गया हो तो मामला और गंभीर हो जाता है,इसलिए केवल कार्यालयीन रिकॉर्ड देखकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होगा। विवादित मतदाताओं के वास्तविक निवास स्थान का भौतिक सत्यापन और संबंधित आवेदन तथा दस्तावेजों की जांच भी जरूरी है।

प्रदीप गुप्ता ने रखीं पांच प्रमुख मांगें

कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत पत्र में प्रदीप गुप्ता ने मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रमुख मांगें रखी हैं, पहली मांग दावा-आपत्ति की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ाने की है,शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रारंभिक मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों के स्थानांतरण और गलत वार्ड में नाम दर्ज होने की शिकायतों को देखते हुए मौजूदा अवधि पर्याप्त नहीं है,उन्होंने अवकाश और अन्य कारणों से प्रभावित लोगों को अपने नामों में सुधार कराने तथा आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की है,दूसरी मांग प्रत्येक शिकायत का अनिवार्य फील्ड वेरिफिकेशन कराने की है, शिकायत में कहा गया है कि केवल कार्यालयीन रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेने के बजाय संबंधित मतदाताओं के वास्तविक निवास स्थान का भौतिक सत्यापन कराया जाए, तीसरी मांग गलत वार्ड में दर्ज मतदाताओं के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने की है,ताकि जिन मतदाताओं के नाम गलत वार्ड में दर्ज हुए हैं,वे नियमों के तहत अपने नाम का सुधार करा सकें और किसी पात्र मतदाता का मतदान अधिकार प्रभावित न हो,चौथी मांग नाम जोड़ने, हटाने और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरण की प्रक्रिया की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराने की है, शिकायतकर्ता ने किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव, पक्षपात अथवा नियमविरुद्ध कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की है,पांचवीं मांग संशोधित मतदाता सूची पर दोबारा दावा-आपत्ति का अवसर देने की है, उनका कहना है कि शिकायतों का निराकरण और आवश्यक सुधार करने के बाद संशोधित सूची प्रकाशित की जाए तथा उस पर भी दावा-आपत्ति का अवसर दिया जाए।

शिकायत के बाद निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने दिया जांच का निर्देश

इस शिकायत पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी सामने आई है, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, स्थानीय निर्वाचन,बैकुंठपुर की ओर से 1 नवंबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा पंजीयन अधिकारी,बैकुंठपुर एवं शिवपुर-चरचा को पत्र जारी किया गया, पत्र में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के 30 अक्टूबर 2026 के शिकायत पत्र का संदर्भ देते हुए संबंधित शिकायत का अवलोकन कर जांच करने,नियमानुसार कार्रवाई करने और प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं,यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिकायत को केवल राजनीतिक आरोप मानकर छोड़ने के बजाय निर्वाचन कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों से जांच और प्रतिवेदन मांगा है,अब यह देखना होगा कि जांच में किन वार्डों में कितने नामों को लेकर आपत्तियां सामने आती हैं और उनका निराकरण किस प्रकार किया जाता है।

दावा-आपत्ति की तारीख को लेकर भी महत्वपूर्ण स्थिति

शिकायत पत्र में दावा-आपत्ति की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ाने की मांग की गई थी, वहीं,1 नवंबर 2026 को जारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग के संशोधित आदेश क्रमांक एक-53-1/तीन(दो)/न.पा./निर्वा. नाम/ 2026/1 190,दिनांक 30 अक्टूबर 2026 का उल्लेख है। इस पत्र के अनुसार नगरपालिकाओं की मतदाता नामावली के लिए दावा-आपत्ति की अवधि 3 नवंबर 2026 तक बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई है,इस प्रकार शिकायतकर्ता की 10 नवंबर तक अवधि बढ़ाने की मांग की है, इसलिए इस संबंध में आगे की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना

अब जांच की निष्पक्षता पर टिकी नजरें

बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर उठा यह विवाद प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है, मतदाता सूची ही चुनाव की बुनियाद होती है,यदि प्रारंभिक सूची में नामों की त्रुटियां, गलत वार्ड में प्रविष्टियां या अनियमित स्थानांतरण की शिकायतें हैं तो उनका समय रहते निराकरण होना चाहिए,सबसे जरूरी यह है कि शिकायत में जिन वार्डों और मतदाताओं का उल्लेख किया गया है,उनका निष्पक्ष सत्यापन कराया जाए, यह भी देखा जाए कि नाम जोड़ने अथवा स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किसने दिया,किस दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हुई और संबंधित मतदाता का वास्तविक निवास किस वार्ड में है,यदि कहीं नियमों के विपरीत नाम जोड़ने या स्थानांतरित करने की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए,मतदाता सूची में एक नाम की गलती भी किसी नागरिक के मताधिकार को प्रभावित कर सकती है, जबकि बड़े पैमाने पर अनियमितता की पुष्टि होने पर पूरे चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं,इसलिए बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा की मतदाता सूची की शिकायत को महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखा जा सकता,अब जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाएं,ताकि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध और विवादमुक्त हो सके।

रामलीला मैदान में गूंजा 'वोट चोर गद्दी छोड़',राहुल गांधी के साथ कोरिया कांग्रेस ने भी बुलंद की आवाज

-संवाददाता-

दिल्ली/कोरिया,02 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से 1 नवंबर 2026, रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोर गद्दी छोड़' कार्यक्रम में कोरिया जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई,राहुल गांधी के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बिहारी लाल राजवाड़े सहित जिले के अनेक जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, कार्यक्रम में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिबद्धता जताई, पार्टी की ओर से यह संदेश दिया गया कि देश का संविधान सर्वोपरि है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए जनता की आवाज को मजबूती से उठाना जरूरी है, 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे के माध्यम से कांग्रेस ने मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर अपने सवाल राष्ट्रीय मंच पर उठाए,रामलीला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए कोरिया जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लोकतंत्र एवं संविधान रक्षा अभियान में अपनी भागीदारी दर्ज कराई,जिले से पहुंचे प्रतिनिधियों ने एक स्वर में संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संदेश को आगे बढ़ाया।

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया





दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता,कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल और ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी लाल राजवाड़े सहित जिले के अनेक नेता-कार्यकर्ता हुए शामिल

प्रदीप गुप्ता की मौजूदगी में कोरिया कांग्रेस ने उठाया लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में कोरिया जिले के कांग्रेस प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की,

बिहारी लाल राजवाड़े सहित ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे दिल्ली

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बिहारी लाल राजवाड़े सहित जिले के अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए,उनकी सहभागिता को जिले के संगठनात्मक स्तर पर पार्टी के अभियान के समर्थन के रूप में देखा गया,कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।

रामलीला मैदान से उठा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की ओर से यह संदेश दिया गया कि हिंदुस्तान की आवाज लोकतंत्र और संविधान को कमजोर नहीं होने देगी,संविधान देश की सर्वोच्च व्यवस्था है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है,कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे के साथ चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर अपनी राजनीतिक आवाज बुलंद की।

जिला स्तर पर संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़े पार्टी के अभियान में भागीदारी दर्ज कराई,कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही रहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

अशोक जायसवाल ने भी दर्ज कराई सहभागिता–

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल भी रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जायसवाल ने कोरिया जिले के कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में भागीदारी की,कार्यक्रम में चुनावी निष्पक्षता और मताधिकार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।

कोरिया से पहुंचे अनेक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल, सत्यप्रकाश तिवारी,पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामकृष्ण साहू,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती मरकाम,पूर्व सभापति जनपद पंचायत खड़गवां नरेश जायसवाल,शीतल प्रसाद सिंह, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय सिंह,मंडल अध्यक्ष रामसाय सोरी, मोहन यादव एवं बसंत सिंह,कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष स्वतंत्र महोबिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बिहारी लाल राजवाड़े,संगीता राजवाड़े,रविशंकर राजवाड़े,रकीबा बेगम,पार्षद वाशिम खान,दिलबंधु यादव,मंडल अध्यक्ष राजू भगत,रामकुमार यादव,संतोष सिंह, लालदास महंत,नीता डे,निखिल कुमार कुशवाहा,रामकुमार सिंह सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित रहे।



जिला अस्पताल का ड्राइवर या डायरेक्टर? जीवनदीप की नियुक्ति पर सवाल...अस्पताल के कामकाज में कथित दखल की चर्चा

एंबुलेंस चलाने की जिम्मेदारी या अस्पताल चलाने का अधिकार ? जिला अस्पताल में युवक की भूमिका पर सवाल

जीवनदीप का कर्मचारी या अस्पताल का सुपर बॉस? आपातकालीन कक्ष की वायरल तस्वीर ने उठाए सवाल...

ड्राइवर की नियुक्ति,अस्पताल में कथित दखल! जिला अस्पताल की व्यवस्था पर कौन रखेगा नजर?

आपातकालीन कक्ष में मरीज के उपचार तक पहुंचा एंबुलेंस चालक? नियुक्ति और अधिकारों की जांच जरूरी

जिला अस्पताल में किसका चलता है आदेश? जीवनदीप से नियुक्त युवक की भूमिका पर उठे सवाल...

एंबुलेंस चालक की जिम्मेदारी छोड़ दूसरे कार्यों में सक्रिय रहने का आरोप,आपातकालीन कक्ष में मरीज का उपचार करते वायरल फोटो ने बढ़ाए सवाल...

आखिर किस पद और अधिकार से अस्पताल में कर रहा हस्तक्षेप?

- रवि सिंह-

बैकुंठपुर,02 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिला अस्पताल में इन दिनों एक ऐसे युवक की भूमिका चर्चा का विषय बनी हुई है,जिसकी नियुक्ति कथित तौर पर एंबुलेंस चालक के रूप में बताई जाती है,लेकिन अस्पताल परिसर में उसकी सक्रियता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं,अस्पताल के विभिन्न कार्यों में कथित हस्तक्षेप से लेकर चिकित्सकों और जनप्रतिनिधियों के बीच उसकी सक्रिय मौजूदगी तक, युवक की भूमिका को लेकर अस्पताल के भीतर और बाहर चर्चाएं होने की बात सामने आ रही है,सवाल यह है कि आखिर युवक की वास्तविक जिम्मेदारी क्या है? क्या उसकी नियुक्ति केवल एंबुलेंस संचालन के लिए हुई है या जीवनदीप समिति के माध्यम से उसे कोई अन्य जिम्मेदारी भी सौंपी गई है?

मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई,जिसमें उक्त युवक को आपातकालीन कक्ष में एक मरीज के उपचार से जुड़ी गतिविधि में देखा जा रहा है,इस तस्वीर ने अस्पताल की कार्यप्रणाली और मरीजों के उपचार में अधिकृत चिकित्सा कर्मियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं,यदि युवक चिकित्सकीय कार्य कर रहा था तो किसकी अनुमति से और किस योग्यता के आधार पर? क्या अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी थी? या फिर किसी कर्मचारी को अपनी निर्धारित जिम्मेदारी से आगे बढ़कर दूसरे कार्य करने की खुली छूट मिली हुई है?

नियुक्ति एंबुलेंस चालक की, लेकिन सक्रियता दूसरे कामों में?

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि बैकुंठपुर निवासी यह युवक कई वर्षों से जिला अस्पताल में सक्रिय है,उसकी नियुक्ति जीवनदीप समिति के माध्यम से किस पद पर हुई है और उसके कार्यों का दायरा क्या निर्धारित किया गया है, यह स्पष्ट होना जरूरी है,यदि वह एंबुलेंस चालक है तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी मरीजों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने और निर्धारित एंबुलेंस संचालन से जुड़ी होनी चाहिए,लेकिन आरोप हैं कि युवक अस्पताल के दूसरे कार्यों में भी हस्तक्षेप करता है,अस्पताल के विभिन्न विभागों में उसकी सक्रियता और अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच उसकी मौजूदगी को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं,कुछ कर्मचारियों के असहज होने की बातें भी सामने आ रही हैं, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित कर्मचारियों के बयान अभी सामने आना बाकी है,ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि युवक की नियुक्ति किस पद पर हुई, उसे कौन-कौन से कार्य सौंपे गए हैं और क्या उसे निर्धारित जिम्मेदारी से अलग किसी अन्य प्रशासनिक अथवा चिकित्सकीय कार्य में लगाया गया है?

आपातकालीन कक्ष में मरीज का उपचार,वायरल तस्वीर ने बढ़ाई चिंता

इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू सोशल मीडिया पर वायरल वह तस्वीर है,जिसमें युवक को आपातकालीन कक्ष में मरीज के उपचार से जुड़ी गतिविधि करते हुए देखा जा रहा है,तस्वीर की वास्तविक परिस्थिति, समय और युवक की भूमिका की पुष्टि होना अभी बाकी है,लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा किया है कि अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में मरीजों की देखभाल और उपचार की जिम्मेदारी किसकी है? आपातकालीन कक्ष किसी भी अस्पताल का अत्यंत संवेदनशील हिस्सा होता है, यहां मरीजों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है,ऐसे में मरीज के उपचार से जुड़ा प्रत्येक कार्य निर्धारित योग्यता,प्रशिक्षण और अधिकृत चिकित्सकीय जिम्मेदारी के अनुरूप ही होना चाहिए, यदि वायरल तस्वीर में दिखाई दे रही गतिविधि चिकित्सकीय उपचार से संबंधित है तो अस्पताल प्रबंधन को इसकी जांच कर स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित युवक को ऐसा कार्य करने की अनुमति किसने दी थी? क्या वह किसी चिकित्सक या अधिकृत चिकित्सा कर्मी के निर्देश पर सहायता कर रहा था अथवा अपने स्तर पर मरीज के उपचार में शामिल था? दोनों परिस्थितियों में वास्तविक भूमिका सामने आना जरूरी है,सिर्फ तस्वीर के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना उचित नहीं होगा,लेकिन तस्वीर में दिखाई दे रही गतिविधि की पुष्टि और उसकी परिस्थितियों की जांच अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है।

चिकित्सकों और कर्मचारियों के बीच कथित प्रभाव की चर्चा

युवक को लेकर एक अन्य चर्चा अस्पताल के अधिकारियों, चिकित्सकों और कर्मचारियों के बीच उसकी कथित सक्रिय भूमिका को लेकर है,आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह अस्पताल में आने वाले जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक व्यक्तियों की आवभगत में भी सक्रिय रहता है, इससे अस्पताल परिसर में उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बन गई है,जिसकी मौजूदगी केवल एंबुलेंस संचालन तक सीमित नहीं दिखाई देती,कुछ लोगों का दावा है कि अस्पताल के भीतर उसके हस्तक्षेप को लेकर कर्मचारी असहज महसूस करते हैं, लेकिन खुलकर बोलने से बचते हैं,हालांकि,इन दावों की पुष्टि के लिए संबंधित कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने आना आवश्यक है,यहां सवाल किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत सक्रियता का नहीं,बल्कि संस्थागत व्यवस्था का है। जिला अस्पताल किसी व्यक्ति विशेष की निजी व्यवस्था नहीं है। यहां हर कर्मचारी और संविदा कर्मी की जिम्मेदारी,अधिकार और कार्यक्षेत्र निर्धारित होना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को उसके पद से अलग अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है तो उसका लिखित आदेश और कार्यविभाजन भी स्पष्ट होना चाहिए।

जीवनदीप समिति की नियुक्ति और कार्यविभाजन सार्वजनिक हो

जिला अस्पताल में जीवनदीप समिति के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति और व्यवस्था की जाती है। ऐसे में संबंधित युवक की नियुक्ति का आदेश,पदनाम,कार्यविभाजन और सेवा संबंधी शर्तें सामने आनी चाहिए,क्या युवक की नियुक्ति एंबुलेंस चालक के रूप में हुई है? यदि हां,तो क्या उसे अस्पताल के अन्य विभागों में काम करने का कोई लिखित आदेश दिया गया है? क्या उसे मरीजों की देखभाल या उपचार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति है? यदि ऐसी कोई अनुमति नहीं है तो आपातकालीन कक्ष में उसकी मौजूदगी और गतिविधि की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इन सवालों का जवाब अस्पताल प्रबंधन को देना चाहिए। इससे न केवल युवक की वास्तविक जिम्मेदारी स्पष्ट होगी,बल्कि अस्पताल में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र और जवाबदेही को लेकर भी स्थिति साफ होगी।

सवालों के घेरे में अस्पताल की व्यवस्था,जवाब का इंतजार

जिला अस्पताल आम नागरिकों के उपचार और जीवन रक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है,यहां आने वाले मरीज और उनके परिजन यह उम्मीद लेकर पहुंचते हैं कि उन्हें योग्य चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों से उपचार मिलेगा,ऐसे में किसी कर्मचारी की भूमिका को लेकर उठे सवालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता,यदि युवक केवल एंबुलेंस चालक के पद पर नियुक्त है तो उसके कार्यक्षेत्र की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए,यदि उसे कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है तो उसका आदेश सामने आना चाहिए,और यदि आपातकालीन कक्ष में मरीज के उपचार से जुड़ी गतिविधि में उसकी भूमिका नियमों के विपरीत पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए, आखिर जिला अस्पताल में एंबुलेंस चालक की जिम्मेदारी क्या है और अस्पताल के भीतर उसकी वास्तविक भूमिका क्या बन गई है? क्या जीवनदीप समिति ने उसे किसी विशेष पद पर नियुक्त किया है या फिर अस्पताल प्रबंधन की ओर से उसे अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं? इन सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है, अस्पताल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सक्रियता से नहीं, बल्कि निर्धारित जिम्मेदारियों, चिकित्सकीय योग्यता और संस्थागत अनुशासन से चलता है, मरीजों की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की चुप्पी के बजाय स्पष्ट जवाब और निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा रही है।

सीएस और अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी भी तय हो

जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सहित संबंधित प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में रहकर काम करे,अस्पताल की व्यवस्था किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान,राजनीतिक संपर्क या अधिकारियों से निकटता के आधार पर संचालित नहीं हो सकती,यदि किसी कर्मचारी अथवा संविदा कर्मी की भूमिका निर्धारित कार्यों से आगे बढ़ रही है तो प्रबंधन को उसका संज्ञान लेना चाहिए, विशेषकर मरीजों के उपचार से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए,इसलिए अस्पताल प्रबंधन को संबंधित युवक की नियुक्ति और कार्यविभाजन के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए,वायरल तस्वीर की वास्तविकता और परिस्थितियों की पड़ताल कर यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या संबंधित गतिविधि किसी अधिकृत चिकित्सक के निर्देश पर हुई थी।

अस्पताल का निर्माण,लेकिन मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल! खड़गवां में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था कठघरे में,हेलमेट,सेफ्टी बेल्ट और अन्य उपकरणों की उपलब्धता की जांच जरूरी,श्रम विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,02 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। क्षेत्र में निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप है कि खड़गवां क्षेत्र में कई निर्माण स्थलों पर ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा के निर्धारित मानकों की अनदेखी कर काम कराया जा रहा है। इसका एक उदाहरण खड़गवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में देखने को मिल रहा है, जहां मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, निर्माण कार्य की प्रगति के बीच यह जानना जरूरी है कि वहां काम करने वाले श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण स्थल पर मजदूरों को हेलमेट, सुरक्षा जूते, दस्ताने, सेफ्टी बेल्ट और अन्य जरूरी उपकरण दिए जा रहे हैं या नहीं? विशेषकर ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होना आवश्यक है, यदि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से काम कराया जा रहा है तो यह उनकी जान को जोखिम में डालने वाली गंभीर लापरवाही है।

भवन निर्माण की जिम्मेदारी के साथ मजदूरों की सुरक्षा भी जरूरी

किसी भी निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की जिम्मेदारी केवल तय समय में भवन तैयार करना नहीं होती, बल्कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उसका महत्वपूर्ण दायित्व है, निर्माण स्थल पर ऊंचाई से गिरने, भारी सामग्री की चपेट में आने और विद्युत उपकरणों से दुर्घटना होने जैसी आशंकाएं बनी रहती हैं, ऐसे में सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उनका उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है,



विडंबना यह है कि जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए किया जा रहा है, उसी के निर्माण में लगे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आखिर निर्माण की गति और समयसीमा के बीच मजदूरों की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है?

श्रम विभाग की निगरानी आखिर कहां है?-

इस मामले में श्रम विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आखिर खड़गवां क्षेत्र में संचालित निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है या नहीं? क्या श्रम विभाग के अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की जांच की है? यदि निरीक्षण हुआ है तो कमियां मिलने पर क्या कार्रवाई की गई? श्रम विभाग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्षेत्र के अन्य निर्माणाधीन भवनों में श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं,केवल किसी दुर्घटना के बाद जांच और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने के बजाय दुर्घटना रोकने के लिए पहले से प्रभावी निगरानी जरूरी है।

हादसे का इंतजार या समय रहते कार्रवाई?

मजदूर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए निर्माण स्थलों पर मेहनत करते हैं, उनकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामों के बिना काम कराना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, यदि किसी निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है तो संबंधित ठेकेदार और निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, अब मांग उठ रही है कि श्रम विभाग खड़गवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित क्षेत्र के सभी निर्माणाधीन भवनों का औचक निरीक्षण करे, मजदूरों को उपलब्ध कराए जा रहे सुरक्षा उपकरणों, ऊंचाई पर काम करने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुरक्षा उपायों की जांच की जाए,नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जिम्मेदार ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, सवाल सीधा है–क्या श्रम विभाग किसी बड़ी दुर्घटना के बाद जागेगा या समय रहते निर्माण स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराएगा? अस्पताल की इमारत बनाने वाले मजदूरों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी उस भवन में भविष्य में उपचार कराने आने वाले मरीजों की,विकास के नाम पर श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए।

दीपावली से पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सक्रियता,चिरमिरी में मिठाई दुकानों और होटलों का सघन निरीक्षण

जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए...

-संवाददाता-

एमसीबी,02 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

दीपावली त्यौहार के मद्देनजर आम नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार प्रदेशभर में विशेष सघन प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े एवं सीएमएचओ के मार्गदर्शन में विभागीय टीम द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

इसी कड़ी में 30 एवं 31 अक्टूबर 2026 को चिरमिरी क्षेत्र की विभिन्न मिठाई दुकानों एवं खोवा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।



खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविकांत गुप्ता एवं उनकी टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से मिठाई एवं खोवा के नमूने संकलित किए।

निरीक्षण के दौरान बीकानेर स्वीट्स से बेसन लड्डू एवं सोनपापड़ी, केरला होटल से चमचम, बिज्जू होटल से खोवा, राहुल मिष्ठान भंडार से खोवा एवं रसगुल्ला तथा पटेल स्वीट्स से मगज लड्डू के नमूने संकलित किए गए। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।







सारंग के पांच हेलीकॉप्टरों के रोमांचकारी करतबों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

राज्यपाल रमेन डेका ने आसमान में देखा भारतीय वायु सेना का अद्भुत शौर्य,साहस और कौशल

आकाशगंगा के स्काईडाइवर्स और गरुड़ कमांडोज ने भी दिखाया अदम्य साहस

रायपुर,02 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर नवा रायपुर का आसमान आज भारतीय वायु सेना के अदम्य शौर्य,साहस,अनुशासन और अद्भुत उड़ान कौशल का साक्षी बना। सेंध लेक में आयोजित भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सारंग एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम के भव्य एयर-शो में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। इस अवसर पर आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम, गरुड़ कमांडोज और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के जांबाजों ने अपने साहसिक करतबों, सटीक नियंत्रण और उत्कृष्ट समन्वय से उपस्थित जनसमूह को रोमांचित कर दिया। पांच हेलीकॉप्टरों की आकर्षक फॉर्मेशन, हैरतअंगेज हवाई करतबों, आसमान में तिरंगे की मनमोहक छटा और 'वंदे मातरम' की गूंज ने पूरे वातावरण को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से सराबोर कर दिया। राज्यपाल रमेन डेका ने भारतीय वायु सेना के जांबाजों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित सारंग टीम का यह आयोजन हम सभी के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है। वायु वीरों ने जिस साहस, अनुशासन,आत्मविश्वास और सटीक समन्वय के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया है,वह प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। यह आयोजन केवल रोमांचकारी हवाई करतबों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारतीय वायु सेना की उत्कृष्ट क्षमता,कठिन प्रशिक्षण, समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना का जीवंत परिचय है। उन्होंने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कामना की,कि हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस की खुशियों के बीच भारतीय वायु सेना के जांबाजों का यह अद्भुत प्रदर्शन प्रदेशवासियों के उत्साह और गौरव को और अधिक बढ़ा रहा है।

आकाशगंगा के जांबाजों ने आसमान से उतरकर दिखाया अद्भुत साहस और सटीक नियंत्रण : एयर-शो का रोमांचकारी शुभारंभ भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम ने किया। खुले आसमान से छलांग लगाते हुए टीम के जांबाजों ने अपने पैराशूट को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर अदम्य साहस,संतुलन और सटीकता का परिचय दिया। निर्धारित दिशा और गति के अनुरूप पैराशूट को नियंत्रित करते हुए स्काईडाइवर्स ने सेंध लेक के सामने निर्धारित स्थान पर सटीक लैंडिंग की। उनके इस साहसिक प्रदर्शन को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे और सफल लैंडिंग के बाद पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रस्तुति ने भारतीय वायु सेना के जवानों की शारीरिक दक्षता, मानसिक एकाग्रता और दृढ़ता और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की प्रभावशाली झलक प्रस्तुत की।

गरुड़ कमांडोज ने किया रेस्क्यू और कॉम्बैट ऑपरेशन का प्रभावशाली प्रदर्शन : आकाशगंगा टीम के प्रदर्शन के बाद भारतीय वायु सेना के गरुड़ कमांडोज ने अपने अदम्य साहस और विशेष ऑपरेशन की दक्षता का परिचय दिया। कमांडोज ने एयर-शो से पहले आठ हजार फीट की ऊंचाई से पैराशूट लैंडिंग कर दर्शकों को रोमांचित किया। इसके पश्चात एमआई-17 हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग का प्रदर्शन किया गया। हवा में स्थिर हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे नीचे उतरते जवानों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्धारित स्थान तक पहुंचने की अपनी दक्षता प्रदर्शित की। सेंध लेक के सामने कमांडोज ने रेस्क्यू एवं कॉम्बैट ऑपरेशन का प्रभावशाली प्रदर्शन कर अपनी परिचालन क्षमता,त्वरित कार्रवाई और कठिन परिस्थितियों में मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के कौशल का परिचय दिया। इसके पश्चात जवानों ने मंच को सलामी दी। उनके अनुशासित और साहसिक प्रदर्शन पर दर्शकों ने तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। एयर-शो का सबसे प्रमुख आकर्षण भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की शानदार प्रस्तुति रही। ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार के नेतृत्व में टीम के पांच हेलीकॉप्टरों ने नवा रायपुर के आसमान में एक के बाद एक आकर्षक फॉर्मेशन और रोमांचकारी हवाई करतब प्रस्तुत किए। पायलटों ने अत्यंत सटीक नियंत्रण,संतुलन और बेहतरीन समन्वय के साथ हेलीकॉप्टरों को उड़ाकर अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया। आसमान में एक साथ उड़ते पांच हेलीकॉप्टरों की आकर्षक फॉर्मेशन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कभी हेलीकॉप्टर एक-दूसरे के बेहद करीब आते दिखाई दिए,तो कभी अलग-अलग दिशाओं में उड़ान भरते हुए पुनः निर्धारित फॉर्मेशन में एक साथ आ गए। प्रदर्शन के दौरान हेलीकॉप्टरों का बेहद नजदीक से एक-दूसरे को क्रॉस करने वाला रोमांचकारी 'क्रॉसओवर' करतब विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। तेज गति से एक-दूसरे के सामने से गुजरते हेलीकॉप्टरों को देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। इस करतब में पायलटों के मन की एकाग्रता, उड़ान पर नियंत्रण और आपसी तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला।

अनुशासन, आपसी विश्वास और टीम भावना का अनुपम उदाहरण है सारंग टीम

राज्यपाल डेका ने कहा कि सारंग का अर्थ मोर होता है। जिस प्रकार मोर हमारे देश की विशिष्ट पहचान और सुंदरता का प्रतीक है, उसी प्रकार सारंग टीम भारतीय वायु सेना की गरिमा, उत्कृष्ट कौशल और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हवाई प्रदर्शन के दौरान हेलीकॉप्टरों की विभिन्न फॉर्मेशन और साहसिक करतब भले ही देखने में सहज और सुंदर दिखाई देते हों, लेकिन इनके पीछे विस्तृत योजना, निरंतर अभ्यास, गहरी एकाग्रता और असाधारण समन्वय होता है। प्रत्येक पायलट को अपनी भूमिका के साथ-साथ अपने साथियों की गतिविधियों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक-दूसरे पर अटूट विश्वास और सटीक तालमेल ही ऐसी अद्भुत प्रस्तुतियों को संभव बनाता है। उन्होंने कहा कि सारंग टीम का प्रदर्शन हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अनुशासन, समर्पण, सामूहिक प्रयास और आपसी विश्वास से कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रदर्शन युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने और सामूहिक प्रयासों से सफलता हासिल करने की प्रेरणा देता है।

सारंग के कॉकपिट से गूंजा 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया', दर्शकों का उत्साह हुआ दोगुना

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सारंग टीम ने प्रदेश के प्रति अपने विशेष स्नेह और सम्मान का भी परिचय दिया। हवाई प्रदर्शन के दौरान ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार ने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय उद्घोष 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' के माध्यम से प्रदेशवासियों का आत्मीय अभिवादन किया। आसमान से गूंजे इस उद्घोष ने उपस्थित जनसमूह के उत्साह को दोगुना कर दिया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय वायु सेना के जांबाजों द्वारा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान और जनभावनाओं को सम्मान देने का यह क्षण दर्शकों के लिए विशेष रूप से यादगार बन गया।

तिरंगे की मनमोहक फॉर्मेशन और 'वंदे मातरम्' की गूंज से देशभक्ति के रंग में रंगा आसमान

हवाई प्रदर्शन के अंतिम चरण में सारंग टीम ने 'वंदे मातरम्' गीत की गूंज के बीच तिरंगे की मनमोहक फॉर्मेशन प्रस्तुत की। आसमान में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा, हेलीकॉप्टरों का अद्भुत तालमेल और देशभक्ति गीत की गूंज ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया।

शौर्य,साहस,अनुशासन और राष्ट्रप्रेम से परिपूर्ण इस प्रस्तुति के साथ एयर-शो का भव्य एवं यादगार समापन हुआ। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने प्रदेशवासियों को भारतीय वायु सेना की उत्कृष्टता और राष्ट्रसेवा के गौरवशाली स्वरूप को निकट से देखने का अवसर प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम विश्व की एकमात्र पांच हेलीकॉप्टरों वाली एयरोबेटिक प्रदर्शन टीम है। यह टीम अपने सुनियोजित हवाई करतबों,आकर्षक फॉर्मेशनों और अद्भुत उड़ान कौशल के माध्यम से भारतीय वायु सेना की सटीकता,अनुशासन,व्यावसायिकता तथा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का परिचय देती है। सारंग टीम जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम,मॉरिशस, रूस और मिस्र सहित दुनिया के अनेक देशों में अपने शानदार 1500 हवाई प्रदर्शनों से भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को नई ऊंचाइयां प्रदान कर चुकी है।

छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विजन को वैश्विक शिखर सम्मेलन में रखेंगे विष्णु देव साय



रायपुर,02 नवम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को भारत मंडपम में आयोजित इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। समिट में मुख्यमंत्रियों एवं केंद्रीय मंत्रियों की राउंड टेबल चर्चा आयोजित की जाएगी। इस वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विजन को प्रमुखता से प्रस्तुत करेंगे। उनका जोर राज्य को ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक केंद्र के साथ-साथ स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने पर रहेगा। छत्तीसगढ सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य की प्राकृतिक संसाधन क्षमता,ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं, ग्रीन एनर्जी के विस्तार और भविष्य की निवेश योजनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री का विजन छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने के साथ-साथ देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन, आधुनिक ऊर्जा अधोसंरचना का विकास और निजी निवेश की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल रहेगा। मुख्यमंत्री निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं तथा निवेश के अनुकूल वातावरण की जानकारी भी साझा करेंगे। उनका प्रयास राज्य की ऊर्जा क्षमता को नए निवेश,रोजगार और औद्योगिक विकास के अवसरों में बदलना है।

महादेव सट्टा,सौरभ चंद्राकर को रायपुर लाएगी सीबीआई

दिल्ली कोर्ट से मिली 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड, स्पेशल कोर्ट में करेगी पेश

रायपुर,02 नवम्बर 2026। 6 हजार करोड़ के महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लेकर आई है। सोमवार को उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि आरोपी को 4 नवंबर 2026 या उससे पहले रायपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाए। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई को सौंपी थीं। इनमें से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर सीबीआई को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन मनी किन-किन लोगों तक पहुंचती थी, इसका बड़ा खुलासा होगा।



प्रत्यर्पण को लेकर आरोपी के वकील ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर के वकील ने ओमान की अदालत के आदेश का हवाला देते हुए सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि भारत की ओर से ओमान को प्रत्यर्पण के लिए जो अनुरोध भेजा गया था, उसमें ईडी के मामले को मंजूरी मिली थी, जबकि सीबीआई के मामले को मंजूरी नहीं दी गई थी। वकील ने दलील दी कि प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक सौरभ पर उन्हीं मामलों में कार्रवाई की जा सकती है, जिनके आधार पर उसे भारत लाया गया है। उन्होंने इसे प्रत्यर्पण के नियमों का उल्लंघन बताया और कहा कि सीबीआई उसे अपने मामले में रिमांड पर नहीं ले सकती।

सीबीआई ने कहा- गिरफ्तारी पर रायपुर कोर्ट फैसला करेगी : सीबीआई की ओर से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत ने पहले ही ओपन एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किया था। ओमान सरकार से मिली जानकारी के आधार पर उसे भारत लाया गया है। सीबीआई ने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई के मामले एक-दूसरे से जुड़े हैं। फिलहाल दिल्ली कोर्ट को सिर्फ यह तय करना है कि आरोपी को रायपुर की अदालत तक ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड दी जाए या नहीं। प्रत्यर्पण की शर्तों और मुकदमा चलाने के अधिकार से जुड़े सवालों पर फैसला रायपुर की विशेष अदालत करेगी।

2022 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है मामला : सीबीआई के मुताबिक,महादेव बुक ऐप को सौरभ चंद्राकर,रवि उप्पल और उनके सहयोगियों ने मिलकर प्रमोट किया था। आरोप है कि ऑनलाइन सट्टे के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म और पैनल बनाए गए थे। इनके जरिए सट्टा संचालित किया जाता था। जांच एजेंसी का आरोप है कि सट्टे से मिलने वाली रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए इकट्ठा किया जाता था। इसके बाद यह पैसा यूएई तक पहुंचाया जाता था। सौरभ और उसके सहयोगियों पर दुबई से इस नेटवर्क को संचालित करने का भी आरोप है। इस नेटवर्क में छत्तीसगढ़ के कई युवाओं को कर्मचारी और मैनेजर के तौर पर काम पर रखने की बात भी जांच में सामने आई है।

दीपावली से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा

आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त,अमित शाह करेंगे राशि ट्रांसफर

रायपुर,02 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की दिशा में महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की माताओं-बहनों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दीपावली से ठीक पहले योजना की नवंबर माह की 33वीं किस्त का अंतरण आज राज्योत्सव समारोह के दौरान किया जाएगा। राज्योत्सव समारोह के मुख्य मंच से गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान प्रदेश की 67 लाख 40 हजार 410 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 632 करोड़ 63 लाख 67 हजार 750 रुपये की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। त्योहार से पहले खाते में राशि आने से महिलाओं और उनके परिवारों में भारी उत्साह और उमंग का माहौल है। ई-केवाईसी पूर्ण करा चुकीं प्रदेशभर की 67 लाख 33 हजार 502 महिला हितग्राही लाभान्वित होंगी।



जोगी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भगवानू नायक ने छोड़ी पार्टी

निजी कारणों का हवाला देकर प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा

रायपुर,02 नवम्बर 2026। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) को झटका लगा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मुख्य प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो डॉ. रेणु जोगी को पत्र भेजकर अपना त्यागपत्र सौंपा है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। भगवानू नायक ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में निजी कारणों से उनके लिए पार्टी को अपेक्षित समय दे पाना संभव नहीं है। इसलिए वे मुख्य प्रवक्ता पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं।

अजीत जोगी के साथ काम करने को बताया अहम अनुभव

भगवानू नायक ने इस्तीफे में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस के संस्थापक स्वर्गीय अजीत जोगी के साथ काम करने के अनुभव को अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। उन्होंने लिखा कि अजीत जोगी के सानिध्य में उन्हें राजनीति, जनसेवा, संघर्ष और छत्तीसगढ़ के हितों के लिए आवाज उठाने की सीख मिली। उन्होंने डॉ. रेणु जोगी से मिले मातृवत स्नेह और अमित जोगी से मिले सम्मान-सहयोग के लिए भी आभार जताया। नायक ने स्पष्ट किया कि पार्टी के पद और सदस्यता से अलग होने के बावजूद जोगी परिवार के प्रति उनका सम्मान और व्यक्तिगत संबंध बने रहेंगे।



बिना किसी शिकायत के दिया इस्तीफा

भगवानू नायक ने पत्र में कहा कि,मुख्य प्रवक्ता के रूप में उन्होंने समाचार चैनलों,सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से पार्टी,छत्तीसगढ़ की जनता और जोगी परिवार का पक्ष रखने का प्रयास किया। उन्होंने पार्टी के साथियों,मीडिया और जनता से मिले सहयोग के लिए आभार भी जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बिना किसी कटुता,शिकायत या व्यक्तिगत मतभेद के पार्टी छोड़ रहे हैं और सुप्रीमो डॉ. रेणु जोगी से उनका इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया है।

छत्तीसगढ़ में जनगणना ड्यूटी वाले कर्मचारियों के तबादले पर 6 महीने की रोक

रायपुर,02 नवम्बर 2026। राज्य सरकार ने जनगणना 2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) के कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अगले छह माह या कार्य पूर्ण होने तक रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य में जनसंख्या गणना का फील्ड कार्य जनवरी-फरवरी 2027 में होना है।

वर्तमान में, 12 अक्टूबर से जिला स्तर पर जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय स्तर पर तथा तहसील स्तर पर प्रभारी अधिकारियों का सघन प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इसके बाद, नवंबर 2026 में मास्टर ट्रेनर्स, 1 दिसंबर से फील्ड ट्रेनर्स और 16 दिसंबर से गणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह, पूरे मैदानी अमले को जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की समस्त प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के निदेशक ने इस संबंध में प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था। पत्र में बताया गया कि जनगणना का यह चरण तकनीकी, समय-सीमाबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ संपादित किया जाना है। प्रशिक्षित अमले के स्थानांतरण से प्रशासनिक और तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

C M Y K

राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव



समापन समारोह 2026

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मुख्य अतिथि
श्री अमित शाह
माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार

अध्यक्षता
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विशिष्ट अतिथि
श्री अरुण साव
माननीय उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री विजय शर्मा
माननीय उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

एवं

समस्त माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, निगम, मंडल, आयोग, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, माननीय महापौर की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित है।

03 नवंबर 2026
सायं 6.00 बजे
राज्योत्सव मैदान, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

सुशासन समृद्धि समावेशी विकास
संवर रहा छत्तीसगढ़

सशक्त नारी युवा उड़ान



पीएम आवास योजना
24.54 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्की छत

रेलवे का विस्तार
₹54,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन

डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा ट्राइबल हेरिटेज व ईको टूरिज्म को बढ़ावा

जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन
बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक, बस्तर पण्डुम का निरंतर आयोजन

महतारी वंदन योजना
68 लाख महिलाओं को ₹20,708 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित

कृषक कल्याणकारी योजनाओं से
₹1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों को अंतरित

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा
बस्तर-सरगुजा के 815 गाँवों तक सुलभ परिवहन सुविधा

शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा
75 सुरक्षा कैंप बन रहे सेवा के केंद्र

1076
सीएम हेल्पलाइन 1076
हर शिकायत की सुनवाई
हर समस्या का समाधान

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार
38 विभागों की 953 सेवाएं
एक ही प्लेटफॉर्म पर

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

संवाद 49677/57

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)